- 20th Year
- Issue: 114
- 25.08.2026 (TUESDAY)
- ROURKELA
- R.N.I. No. ORIHIN/2006/18978
- (Pages-6)
- Price:2.00

दैनिक
कलिंग समाचार
The kalingasamachar

e-paper-www.thekalingasamachar.com

प्रकाशक एवं संपादक : प्रकाश कुमार धल

Published From ODISHA, JHARKHAND & CHHATTISHGARH

सीमा विवाद सुलझाने की दिशा में बड़ा कदम, एनएसए अजीत डोभाल की बीजिंग यात्रा भारत-चीन संबंधों के लिए अहम

नयी दिल्ली २४/०८ (संवाददाता): राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल सोमवार को चीन की राजधानी बीजिंग पहुंच रहे हैं, जहां वे चीनी विदेश मंत्री और अपने समकक्षी वांग यी के साथ भारत-चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों (स्क्र) की 25वें दौर की वार्ता में भाग लेंगे। यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब दोनों देश वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव कम करने और सैन्य गतिरोध को समाप्त करने की दिशा में कूटनीतिक प्रयास तेज कर रहे हैं। आगामी वार्ता इसलिए महत्वपूर्ण है ज़्योंकि यह 12-13 सितंबर को नई दिल्ली में ब्रिज़्स शिखर सज़्मेलन के लिए चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के भारत दौरे से पहले हो रही है। हालांकि शी के दौरे की अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई

है, लेकिन दोनों पक्षों के अधिकारी उनके शामिल होने को लेकर आशावादी हैं।

यह वार्ता ऐसे समय में हो रही है जब भारत और चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा (स्र्ष्ट) पर तनाव कम करने और सैन्य टकराव की स्थिति को शांत करने की दिशा में काम कर रहे हैं। गौरतलब है कि जून 2020 में गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद दोनों देशों के संबंध काफी तनावपूर्ण हो गए थे, जिसके बाद भारत और चीन ने पूर्वी लद्दाख में बड़ी संज़्या में सैनिकों और सैन्य उपकरणों की तैनाती की थी। हाल के वर्षों में, दोनों देशों के बीच सैन्य और राजनयिक स्तर पर कई दौर की वार्ता हुई है। इन वार्ताओं का उद्देश्य स्र्ष्ट से सैनिकों की वापसी, डिसइंगेजमेंट (सैन्य टुकड़ियों का पीछे हटना) और सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करना रहा है।

विशेष प्रतिनिधि तंत्र एक महत्वपूर्ण मंच है जिसे भारत और चीन के बीच सीमा विवाद का राजनीतिक समाधान खोजने के लिए स्थापित किया गया है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और चीन के उनके समकक्ष इस तंत्र के तहत बातचीत करते हैं। इसका उद्देश्य न केवल मौजूदा सैन्य तनाव को कम करना है, बल्कि सीमा विवाद के व्यापक और दीर्घकालिक समाधान के लिए राजनीतिक रास्ता खोजना भी है। ज़्यों बेहद अहम माना जा रहा है यह दौरा ?1. शी जिनपिंग के संभावित भारत दौरे से पहले की पटकथा. यह वार्ता आगामी 12-13 सितंबर को नई दिल्ली में आयोजित होने वाले ब्रिज़्स शिखर सज़्मेलन से ठीक पहले हो रही है। इस सज़्मेलन में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के भारत आने की संभावना जताई जा रही है। डोभाल का यह दौरा दोनों देशों के शीर्ष नेताओं की मुलाकात के लिए अनुकूल माहौल बनाने की दिशा में एक प्रमुख कूटनीतिक कदम है।

2. राजनीतिक समाधान के लिए विशेष प्रतिनिधि (स्क्र) तंत्र

विशेष प्रतिनिधि वार्ता केवल तात्कालिक सैन्य विवादों को सुलझाने का मंच नहीं है, बल्कि यह दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक और व्यापक सीमा समाधान खोजने के लिए स्थापित एक उच्चतम राजनीतिक तंत्र है। गलवान घटना के बाद से दोनों पक्षों के बीच यह राजनीतिक संवाद बेहद निर्णायक मोड़ पर है।

3. कूटनीतिक और सैन्य वार्ता में संतुलन-हाल के वर्षों में भारत और चीन ने कोर कमांडर स्तर की सैन्य वार्ताएं तो की हैं, लेकिन राजनीतिक और रणनीतिक स्तर पर दिशा तय करने के लिए स्क्र वार्ता का होना अनिवार्य माना जाता है। डोभाल की यह यात्रा वार्ता प्रक्रिया को नई गति देगी।

अकाली दल से गठबंधन पर असमंजस के बीच भाजपा का बड़ा ऐलान: पंजाब की सभी ११७ सीटों पर लड़ेंगे चुनाव

नयी दिल्ली २४/०८ (संवाददाता): फरवरी 2027 में होने वाले पंजाब विधानसभा चुनावों के लिए BJP और शिरोमणि अकाली दल के बीच संभावित गठबंधन की बढ़ती चर्चाओं के बीच, क्ष्छ्वक्क के राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) बीएल संतोष ने सोमवार को कहा कि पार्टी राज्य में अपनी सरकार बनाने के मकसद से सभी 117 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पटियाला में राज्य क्ष्छ्वक्क की ज़ोनल बैठक को संबोधित करते हुए संतोष ने कहा कि पंजाब बदलाव के लिए पूरी तरह तैयार है और क्ष्छ्वक्क इस बदलाव को हकीकत में बदलने के लिए पूरी तरह तैयार है। आगामी विधानसभा चुनावों में, क्ष्छ्वक्क पंजाब की सभी 117 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी और जीत हासिल करके राज्य में अपनी सरकार बनाएगी। पश्चिम बंगाल में मिली जीत से उत्साहित क्ष्छ्वक्क

ने पंजाब में पूरी ताकत झोंकने का फ़ैसला किया है। साथ ही, 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले भारतीय जनता पार्टी और शिरोमणि अकाली दल के बीच फिर से गठबंधन की चर्चाएं भी चल रही थी। पार्टी संगठन को मज़बूत करने के मक़सद से, पार्टी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) बीएल संतोष दो दिन के दौरे पर पंजाब पहुंचे हैं। इसी के साथ, भगवा पार्टी ने आज पंजाब में अपनी चुनावी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। पटियाला में हुई पहली ज़ोनल मीटिंग को संबोधित करते हुए संतोष ने कहा कि पंजाब बदलाव के लिए पूरी तरह तैयार है और बीजेपी इस बदलाव को हकीकत में बदलने के लिए पूरी तरह तैयार है। आने वाले विधानसभा चुनावों में, बीजेपी पंजाब की सभी 117 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी और जीत हासिल करके राज्य में अपनी सरकार बनाएगी। संतोष, बीजेपी और उसके मुज़्य संगठन ऋस्स के बीच सबसे अहम कड़ी हैं। बीजेपी के संगठन में राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) का पद ही एकमात्र ऐसा शीर्ष पद है जो ऋस्स नेताओं के लिए आरक्षित है।

बंबीहा गैंग पर अमित शाह कड़ा प्रहार, मलेशिया से डिपोर्ट किए गए तीन कुख्यात गैंगस्टर्स

नयी दिल्ली २४/०८ (संवाददाता): केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार (24 अगस्त) को बताया कि बंबिहा गैंग से जुड़े तीन भगोड़े गैंगस्टरों को मलेशिया से डिपोर्ट किया गया है। इन पर जबरन वसूली, सीमा पार हथियारों की तस्करी और नशीले पदार्थों की तस्करी समेत कई अपराधों के आरोप हैं। उन्होंने कहा कि इन भगोड़ों - जसप्रीत सिंह, अजय सिंह और पवनदीप सिंह - को पकड़कर भारत लाया गया है। एज़्स पर एक पोस्ट में शाह के ऑफ़िस ने कहा कि भारतीय एजेंसियों ने मलेशिया में तीन फ़रार भारतीय गैंगस्टर्स को पकड़ा, उन्हें भारत डिपोर्ट किया और पुलिस कस्टडी में भेज दिया। ये फ़रार अपराधी - जसप्रीत सिंह, अजय सिंह और पवनदीप सिंह - बंबीहा गैंग से जुड़े हैं और उन पर कई

अपराधों का आरोप है, जिनमें रंगदारी, सीमा पार हथियारों और नशीले पदार्थों की तस्करी, और लुधियाना में ग्रेनेड हमले की नाकाम कोशिश शामिल है। गृह मंत्री ने आगे कहा कि भारतीय एजेंसियों ने अकेले 2026 में 51 कुज़्यात अपराधियों को डिपोर्ट करने में मदद की है। पोस्ट में कहा गया मोदी जी के सुरक्षित भारत के विज़न के तहत, हमारी एजेंसियों ने अकेले 2026 में 51 कुज़्यात अपराधियों को डिपोर्ट करने में मदद की है।

इससे पहले मई में, सेंट्रल ज़्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन ने विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय के साथ मिलकर काम करते हुए, संयुक्त अरब अमीरात (श्च) से दो वॉन्टेड भगोड़ों को भारत वापस लाया।

भारतीय और श्च अधिकारियों की मिली-जुली कोशिशों के बाद दोनों आरोपियों को 1 मई, 2026 को वापस लाया गया। कमलेश पारेख एक बड़े विज़ीय धोखाधड़ी मामले में वॉन्टेड थे, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया के नेतृत्व वाले बैंकों के समूह को सैकड़ों करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था। जांचकर्ताओं के अनुसार, उन्होंने कंपनी के अन्य अधिकारियों के साथ मिलकर, कथित तौर पर विदेशी व्यवसायों के एक नेटवर्क के ज़रिए बैंक फंड का गलत इस्तेमाल किया; इस नेटवर्क में श्च में चल रहे कामकाज भी शामिल थे। इस मामले में विज़ीय लेन-देन में हेरफेर और बैंकिंग सिस्टम का गलत इस्तेमाल शामिल है। इंटरपोल रेड नोटिस के ज़रिए श्च में उनका पता लगाया गया और बाद में स्थानीय अधिकारियों ने उन्हें हिरासत में ले लिया। कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद, उन्हें भारतीय अधिकारियों को सौंप दिया गया और दिल्ली लाया गया, जहाँ उन्हें हिरासत में ले लिया गया।

सीएम योगी का अजय राय पर हमला, बोले-भाई के हत्यारे के सामने हुए नतमस्तक, हमने भूसी निकाल दी

लखनऊ २४/०८ (संवाददाता): अयोध्या में यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के कार्यक्रम में मछली भोज को लेकर बड़ा विवाद शुरू हो गया है। रायबरेली में आयोजित %भाव समर्पण समारोह% में मुज़्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस पूरे मामले को लेकर अजय राय पर निशाना साधा है। योगी ने कहा कि आपने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का व्यवहार देखा- वे हनुमानगढ़ी में पूजा-अर्चना करने जाते हैं, लेकिन बाद में बाहर मछली का दावत उड़ाते हैं। वे बाहर कुछ भी खा सकते थे—अयोध्या के अलावा कहीं भी। फिर भी, वे यही दोहरापन दिखाते हैं। इन लोगों को देखकर तो गिरगिट भी शरमा जाए; उसे भी हैरानी होगी कि यह कैसी इंसानी प्रजाति है—जो मंदिर के अंदर %राम-राम% का जाप करती है और बाहर निकलते ही

मछली खाती है। योगी ने अपना हमला जारी रखते हुए कहा कि यही इनका इतिहास है—कांग्रेस के इस प्रदेश अध्यक्ष का इतिहास। जब एक माफिया डॉन ने उनके भाई की हत्या कर दी, तो इस व्यक्ति ने अपराधी के खिलाफ गवाही नहीं दी; बल्कि, वे उसके सामने घुटने टेककर झुक गए। वे उसी आदमी के सामने झुके जिसने बेरहमी से उनके भाई को मार डाला था। हालात तब बदले जब सरकार ने दखल दिया और उस माफिया तत्व को कुचल दिया; वरना, इन लोगों ने राज्य को माफिया-शासित इलाका बना दिया था, जिससे पहचान का संकट पैदा हो गया था। आपको बता दें कि अयोध्या में उज़र प्रदेश कांग्रेस प्रमुख अजय राय के स्वागत कार्यक्रम के दौरान मछली की दावत को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। कुछ स्थानीय धार्मिक हस्तियों ने सावन के पवित्र महीने में खाने के इस इंतज़ाम पर आपज़ि जताई है। हालांकि, कार्यक्रम के आयोजक ने इस फ़ैसले का बचाव करते हुए कहा कि हर व्यक्ति को अपनी पसंद का खाना खाने का संवैधानिक अधिकार है। रविवार को अयोध्या पहुंचे राय ने स्वागत कार्यक्रम में शामिल होने से पहले श्री राम जन्मभूमि मंदिर और हनुमानगढ़ी के दर्शन किए। उन्होंने हनुमानगढ़ी में हनुमान चालीसा का पाठ भी किया।

यह विवाद तब शुरू हुआ जब एक वीडियो सामने आया जिसमें एक बैंक्वेट हॉल में मछली बनाई जा रही थी। इस हॉल में राय, राज्य प्रभारी राजपाल गौतम, राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह और पूर्वांचल प्रभारी अभिषेक दज़ के लिए स्वागत कार्यक्रम आयोजित किया गया था। यह कार्यक्रम कांग्रेस नेता राम निहाल निषाद ने पार्टी में शामिल होने के बाद आयोजित किया था। कार्यक्रम में शामिल होने वाले बड़ी संज़्या में लोगों के लिए खाने-पीने का इंतज़ाम किया गया था।

प्रथम अंतर्राष्ट्रीय राजभाषा वार्षिक शिखर सम्मेलन, ओडिशा-२०२६ का भव्य आयोजन

भुवनेश्वर २४/०८ (संवाददाता): राजभाषा हिंदी के व्यापक प्रचार-प्रसार, प्रगतिशील प्रयोग एवं प्रभावी क्रियान्वयन को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रथम अंतरराष्ट्रीय राजभाषा वार्षिक शिखर सज़्मेलन, ओडिशाङ्क 2026 का आयोजन सीएसआईआर खनिज एवं पदार्थ प्रौद्योगिकी संस्थान (सीएसआईआर-आईएमएमटी), भुवनेश्वर में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, भुवनेश्वर (कार्यालय), नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, भुवनेश्वर (उपक्रम) एवं नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, भुवनेश्वर (बैंक) के संयुक्त तत्वावधान में किया गया। इस गरिमामय आयोजन में महामहिम डॉ. हरि बाबू कंभमपति, माननीय राज्यपाल, ओडिशा मुज़्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में डॉ. रामानुज नारायण, निदेशक, सीएसआईआर-आईएमएमटी एवं अध्यक्ष, नराकास भुवनेश्वर (कार्यालय 02), श्री बृजेंद्र प्रताप सिंह, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, नालको एवं अध्यक्ष, नराकास भुवनेश्वर (उपक्रम), श्री राकेश कुमार यादव, मुज़्य महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, स्थानीय प्रधान कार्यालय, भुवनेश्वर एवं अध्यक्ष, नराकास भुवनेश्वर (बैंक), तथा डॉ. बिपिन कुमार, सदस्य, हिंदी सलाहकार समिति, विज़ मंत्रालय तथा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय सहित अनेक गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। सज़्मेलन के प्रमुख वक्ताओं में श्री राजेश श्रीवास्तव, संयुक्त निदेशक (राजभाषा), गृह मंत्रालय, भारत सरकार; श्री बालेन्दु शर्मा दाधीच, सीईओ, एल्गो टेज़्नोलॉजीज, दुबई तथा पूर्व निदेशक-माइक्रोसॉज़्ट एशिया; प्रो. (डॉ.) पुनीत कुमार द्विवेदी, प्रोफेसर एवं ग्रुप डायरेज़्टर, ऑज़्सफोर्ड इंटरनेशनल कॉलेज, इंदौर; डॉ. राजीव कुमार रावत, वरिष्ठ हिंदी अधिकारी, आईआईटी खड़गपुर; प्रोफेसर (डॉ.) सोमा बंद्योपाध्याय, हिंदी विभाग, कलकज़ा विश्वविद्यालय एवं पूर्व कुलपति, बाबासाहेब अंबेडकर शिक्षा विश्वविद्यालय, पश्चिम बंगाल; तथा डॉ. विवेक मणि त्रिपाठी, एसोसिएट प्रोफेसर, हिंदी विभाग, क्वांगतोंग विदेशी भाषा विश्वविद्यालय, चीन शामिल रहे। लगभग 500 प्रतिभागियों ने सज़्मेलन में सहभागिता की, जिनमें ओडिशा सहित कोलकाता, रांची, पटना, बिहार, झारखंड तथा पूर्वी भारत के विभिन्न क्षेत्रों से केंद्र सरकार के कार्यालयों, सार्वजनिक उपक्रमों, बैंकों एवं अन्य संस्थानों के अधिकारी-कर्मचारी, राजभाषा अधिकारी, शिक्षाविद्, साहित्यकार एवं भाषा विशेषज्ञ शामिल थे। समेलन में राजभाषा हिंदी के

प्रगतिशील प्रयोग, प्रशासनिक कार्यों में हिंदी के प्रभावी उपयोग, तकनीकी एवं डिजिटल युग में हिंदी की संभावनाओं, कृत्रिम बुद्धिमज़ा तथा हिंदी के अंतरराष्ट्रीय विस्तार जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर व्यापक विचार-विमर्श हुआ।

मुज़्य अतिथि महामहिम राज्यपाल डॉ. हरि बाबू कंभमपति ने भारत की भाषाई एवं सांस्कृतिक विविधता, भारतीय भाषाओं के संरक्षण एवं संवर्धन तथा शिक्षा, प्रशासन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और डिजिटल माध्यमों में भारतीय भाषाओं के बढ़ते प्रयोग पर बल दिया। गैर-हिंदी भाषी क्षेत्र ओडिशा में आयोजित यह सज़्मेलन इस बात का सशक्त प्रतीक रहा कि राजभाषा हिंदी का प्रभाव, स्वीकार्यता एवं प्रयोग हिंदीतर राज्यों में भी निरंतर बढ़ रहा है।

डॉ बिपिन कुमार ने कहा कि क्षेत्रीय स्तर क्षेत्रीय भाषा और राष्ट्रीय स्तर राष्ट्रीय भाषा हिंदी होनी चाहिए। हम सभी भारतीय भाषाओं का सज़्मान करते हैं। भाषाएँ एक दूसरे से जोड़ती है। विश्व हिंदी परिषद का मूल उद्देश्य भी यही है कि वह भारत के सभी क्षेत्रीय भाषाओं को साथ लेकर हिंदी को विश्व पटल पर स्थापित हो। इस कार्यक्रम में श्री नन्दकिशोर साह, ओड़िशा प्रांत के अध्यक्ष श्री विक्रमादित्य सिंह, ओड़िशा प्रांत के महामंत्री श्री गोबिंद चौधरी, श्री उमेश प्रजापति, श्री अकाश श्रीवास्तव, श्रीमती स्नेहलता दास, श्री अबिनाश दाश, श्री भगवान बेहरा, सुश्री मौसम तिवारी आदि भी कार्यक्रम के साक्षी बने वहीं श्री नन्दकिशोर साह को हिंदी में अतुलनीय योगदान के लिए भाषा रत्न सज़्मान से सज़्मानित किया गया।

पूर्वी भारत के विभिन्न राज्यों से लगभग 500 प्रतिभागियों की सहभागिता ने हिंदी के प्रति बढ़ती रुचि एवं स्वीकार्यता को प्रदर्शित किया तथा भारतीय भाषाओं के बीच संवाद, समन्वय एवं सांस्कृतिक एकता को मजबूत करने का संदेश दिया। यह सज़्मेलन इस बात का भी सशक्त प्रतीक है कि सीएसआईआर- आईएमएमटी केवल क्रिटिकल मिनरल्स, खनिज एवं पदार्थ प्रौद्योगिकी तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ही अपनी पहचान स्थापित नहीं कर रहा है, बल्कि राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार, प्रगतिशील प्रयोग एवं प्रभावी क्रियान्वयन के क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है।

कार्यक्रम का शुभारंभ गणमान्य अतिथियों के आगमन एवं राष्ट्रगान के साथ हुआ, जिसके पश्चात दीप प्रज्वलन, मंगलाचरण, अतिथि सज़्मान, विभिन्न वक्ताओं के संबोधन एवं पुरस्कार वितरण आयोजित किए गए। समेलन के उपरांत महामहिम राज्यपाल ने सीएसआईआर-आईएमएमटी की प्रयोगशालाओं का भ्रमण किया तथा विशिष्ट अतिथियों के साथ पौधारोपण कार्यक्रम में भी सहभागिता की। कार्यक्रम का प्रभावी एवं गरिमामय मंच संचालन श्री आकाश श्रीवास्तव, कनिष्ठ हिंदी अनुवादक, सीएसआईआर-आईएमएमटी, भुवनेश्वर एवं सदस्य सचिव, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, भुवनेश्वर (कार्यालय-02) द्वारा किया गया। सज़्मेलन ने विभिन्न सरकारी कार्यालयों, सार्वजनिक उपक्रमों, बैंकों, शिक्षण संस्थानों तथा भाषा एवं साहित्य जगत को एक साझा मंच प्रदान करते हुए राजभाषा हिंदी के बढ़ते प्रभाव, भारतीय भाषाओं के बीच संवाद तथा तकनीकी युग में हिंदी के व्यापक उपयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में अपनी पहचान स्थापित की।

विविध समाचार

झारखंड पुलिस ने छात्र प्रदर्शन पर तीन एफआईआर दर्ज की, १०० से अधिक पर शिकंजा

रांची २४/०८ (संवाददाता): झारखंड के गिरिडीह और हजारीबाग में नौकरी के इच्छुक अज़्यर्थियों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस के साथ झड़प के मामले में 39 नामजद और 900 से अधिक अज्ञात लोगों के खिलाफ तीन प्राथमिकी दर्ज की गई हैं। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी। यह घटनाक्रम ऐसे समय हुआ है जब सरकारी काम में बाधा डालने और पुलिस के साथ झड़प करने के आरोप में रांची के कोतवाली थाने में 14 नामजद और 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ शनिवार को तीन प्राथमिकी दर्ज की गई थीं। अधिकारियों ने बताया कि गिरिडीह में शुक्रवार और शनिवार को हुई झड़पों के संबंध में टाउन पुलिस थाने में दो प्राथमिकी दर्ज की गईं, जबकि एक प्राथमिकी हजारीबाग में सरकारी काम में बाधा डालने और पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट के आरोप में दर्ज हुई। शुक्रवार को भर्ती परीक्षा में कथित अनियमितताओं के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हजारों छात्रों ने मुज़्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला फूंकने के लिए गांधी मैदान में जमा होकर प्रदर्शन किया था। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। हजारीबाग सदर के पुलिस उपाधीक्षक रूपक कुमार सिंह ने बताया कि 21 अगस्त को सोरेन का पुतला फूंकने की कोशिश और सरकारी काम में बाधा डालने तथा पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट के आरोप में कोर्रा पुलिस थाने में 18 नामजद और 700 अज्ञात लोगों के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की गई। उन्होंने कहा, ''हमने सदर क्षेत्राधिकारी आशुतोष कुमार की अर्जी के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की है।'' कोर्रा थाना प्रभारी नेमधारी रजक ने बताया कि अभी तक इस मामले में किसी को गिरज़्तार या हिरासत में नहीं लिया गया है। उन्होंने कहा कि पुलिस उपद्रव करने वालों की पहचान के लिए सीसीटीवी और वीडियो फुटेज की जांच कर रही है।

उन्होंने बताया कि कुल आठ पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जिनमें चार उपनिरीक्षक शामिल हैं। उन्होंने बताया कि ये उपनिरीक्षक कोर्रा, लोहसिंघना, सदर और बड़ा बाजार थानों के प्रभारी हैं। उन्होंने कहा कि आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत पुलिसकर्मियों से मारपीट, सरकारी कर्मचारियों के काम में बाधा डालने और गैरकानूनी जमावड़े के आरोप लगाए गए हैं।

गिरिडीह में पहली प्राथमिकी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के कार्यकर्ता अनीश राय के आवेदन पर दर्ज की गई, जबकि दूसरी प्राथमिकी सदर क्षेत्र निरीक्षक (सीआई) मनोज कुमार सिंह की अर्जी पर दर्ज हुई। गिरिडीह टाउन थाना

प्रभारी ने बताया कि पहली प्राथमिकी झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज की गई है। उन्होंने बताया कि इसमें पार्टी के जिलाध्यक्ष संजय सिंह समेत 11 लोगों को नामजद किया गया है, जबकि 20 लोग अज्ञात हैं। उन्होंने बताया कि दूसरी प्राथमिकी में करीब 10 लोगों को नामजद और 200 लोगों को अज्ञात आरोपी बनाया गया है। अधिकारी ने कहा, ''आरोपियों पर पांच स्थानों पर यातायात रोकने की कोशिश करने, मुज़्यमंत्री का पुतला फूंकने से रोकने पर पुलिस से भिड़ने और उनके खिलाफ अभद्र का इस्तेमाल करने के आरोप हैं।'' इस बीच, जेपीएससी-जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच के नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार उन्हें परेशान कर रही है। उन्होंने कहा कि कई सदस्यों के नाम रांची और हजारीबाग दोनों जगह दर्ज प्राथमिकी में हैं और सवाल उठाया कि वे एक ही समय में दोनों स्थानों पर कैसे मौजूद हो सकते हैं।

पीयूष कुमार सिंह ने कहा, ''रांची और हजारीबाग की प्राथमिकी में कुणाल पी. सिंह, रवींद्र प्रसाद और मेरा नाम है... हम एक ही समय में दोनों जगह कैसे मौजूद हो सकते हैं?'' झारखंड विधानसभा में विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी ने सरकार से छात्रों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी वापस लेने की मांग की। उन्होंने पत्रकारों से कहा, अगर सरकार प्राथमिकी वापस नहीं लेती है तो युवाओं को जेल जाने से डरना नहीं चाहिए... जेलें भर दो। जेएनयू छात्रसंघ की पूर्व अध्यक्ष और स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआई) की राष्ट्रीय संयुक्त सचिव आइशी घोष ने भी झारखंड में प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज किए जाने की निंदा की। उन्होंने यहां एसएफआई के नेतृत्व में निकाले गए मार्च के दौरान 'पीटीआई-भाषा' से कहा, ''हम झारखंड में छात्रों के खिलाफ किसी भी तरह की बर्बरता और अत्याचार की निंदा करते हैं।

प्रदर्शन कर रहे छात्रों की मांगें जायज हैं और सरकार को उनकी समस्याओं के समाधान के लिए उनकी बात सुननी चाहिए। संवाद की हमेशा गुंजाइश होती है। छात्र समुदाय के खिलाफ प्राथमिकी और डराने-धमकाने की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए।''

इस बीच, राज्य पुलिस ने रविवार को परामर्श जारी करके कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर धरना, प्रदर्शन, जुलूस, रैली और जनसभाएं आयोजित करने के लिए आयोजकों को पहले अनुमति लेनी होगी और निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होगा।

पुलिस ने छात्रों और आम लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील भी की। छात्र नेताओं ने 11वीं और 13वीं जेपीएससी परीक्षाओं तथा जेएसएससी-सीजीएल के माध्यम से हुई नियुक्तियों को रद्द करने संबंधी कुछ अधिसूचनाओं पर उच्च न्यायालय द्वारा रोक लगाए जाने के बाद राज्य सरकार पर नौकरी के इच्छुक अज़्यर्थियों को धोखा देने और विश्वासघात करने का आरोप लगाया। उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को बाल विकास परियोजना अधिकारियों (सीडीपीओ) और जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा के जरिए नियुक्त लोगों की नियुक्तियां रद्द करने वाली अधिसूचनाओं पर रोक लगा दी थी।

इससे एक दिन पहले बृहस्पतिवार को अदालत ने 11वीं और 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) परीक्षाओं को रद्द करने वाली अधिसूचनाओं पर भी रोक लगा दी थी। अदालत ने खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की नियुक्तियां रद्द करने के आदेश पर भी रोक लगाई थी।

सीजेपी का बड़ा ऐलान, सरकार पर धोखाधड़ी का आरोप, पांच सितंबर को दिल्ली में मार्च

नयी दिल्ली २४/०८ (संवाददाता): कॉकरोच जनता पार्टी ने 5 सितंबर 2026 को नई दिल्ली में शांतिपूर्ण विरोध मार्च निकालने का देशव्यापी आह्वान किया है। पार्टी ने भारत सरकार पर आरोप लगाया है कि उसने 25 जुलाई को युवाओं से किए गए वादों को पूरा नहीं किया। जबकि उन वादों के बाद ही युवाओं ने सद्भावना दिखाते हुए अपना देशव्यापी विरोध प्रदर्शन वापस ले लिया था। 5 सितंबर को होने वाला यह शांतिपूर्ण मार्च इंडिया गेट से शुरू होकर नई दिल्ली पुलिस मुज़्यालय की ओर जाएगा।

इस मार्च का नेतृत्व हश्वश्वञ्ज परीक्षा से जुड़े मामलों में जान गंवाने वाले छात्रों और पुलिस की बर्बरता के शिकार लोगों के परिवार करेंगे। इसमें देश भर से छात्रों, युवा संगठनों और युवा नागरिकों के शामिल होने की उज़्मीद है। इससे पहले कॉकरोच जनता पार्टी ने केंद्र सरकार से कहा है कि वह जंतर-मंतर पर चल रहे विरोध-प्रदर्शन को खत्म करने की कोशिश के तहत प्रेशर ग्रुप से

किए गए वादों को पूरा करे। ऑनलाइन ग्रुप से दबाव बनाने वाले समूह में बदले इस संगठन ने केंद्र पर देश के युवाओं को धोखा देने और उनका भरोसा तोड़ने का आरोप लगाया है।

ष्ट्छक ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि हम सरकार को पूरी पीढ़ी का अपमान नहीं करने देंगे। सरकार शांतिपूर्ण आंदोलन खत्म करने का वादा करती है और फिर जब सड़कें खाली हो जाती हैं, तो उन्हीं वादों से मुकरने की कोशिश करती है। भारत के युवाओं से किए गए वादे को अक्षरश: और उसकी मूल भावना के साथ पूरा किया जाना चाहिए। अपने बयान में ष्ट्छक ने कहा कि छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज स्नह्वक्र को रद्द करने के लिए कोर्ट की बार-बार की गुजारिश के बावजूद, सरकार ने अभी तक कोई लिस्ट नहीं दी है। बयान में कहा गया कि केंद्र सरकार ने इसे उपलज़्ध कराने का कोई वादा नहीं किया था। इसके तुरंत बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ष्ट्छक के सह-संयोजक सौरव दास और कानूनी मामलों की प्रमुख रत्ना सिंह ने चेतावनी दी कि ऐसा लगता है कि सरकार देश की युवा पीढ़ी को धोखा देने की कोशिश कर रही है, जबकि उसने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में किए गए पक्के वादों के आधार पर हमारा आंदोलन वापस करवाया था।

वेस्ट त्रिपुरा में भारी बारिश से हावड़ा और कथाखाल नदियां उफान पर

त्रिपुरा २४/०८ (संवाददाता): वेस्ट त्रिपुरा जिले में शनिवार रात हुई मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है। बार्मुरा पहाड़ियों पर हुई भारी वर्षा के कारण हावड़ा और कथाखाल नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ा, जिससे निचले इलाकों में अचानक बाढ़ (स्नद्यड्डह्यद्ध स्नद्यश्शस्र) आ गई। प्रशासन द्वारा चलाए गए त्वरित राहत और बचाव अभियानों के तहत अब तक 413 परिवारों के 1,305 प्रभावित लोगों को सुरक्षित निकालकर 17 राहत शिविरों में पहुंचाया गया है। अधिकारियों के अनुसार, बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित इलाकों में बालदाखाल, श्रीलंकाबस्ती, कथाखाल और बंबुतिया का एक हिस्सा शामिल है। वेस्ट त्रिपुरा के जिलाधिकारी विशाल कुमार ने संवाददाताओं से कहा, शनिवार रात लगातार हुई भारी बारिश के कारण हावड़ा और कथाखाल नदियों के किनारे स्थित कई निचले इलाकों में पानी भर गया। अब तक 413 परिवारों के कुल 1,305 लोगों को निकालकर 17 राहत शिविरों में पहुंचाया गया है। मुज़्यमंत्री माणिक साहा ने रविवार रात बाढ़ से प्रभावित कुछ इलाकों और राहत शिविरों का दौरा करके हालात का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि सरकार बाढ़ की समस्या को हल करने के लिए स्थायी कदम उठाएगी। मुज़्यमंत्री ने कहा, बार्मुरा पहाड़ियों में भारी बारिश के कारण वेस्ट त्रिपुरा जिले के कई इलाकों में पानी भर गया है। प्रशासन बाढ़ प्रभावित लोगों को हरसंभव सहायता उपलज़्ध कराने में जुटा है।

इसरो की विरासत कमजोर नहीं, रंग ला रही है, कांग्रेस के आरोप पर जितेन्द्र सिंह का पलटवार

नयी दिल्ली २४/०८ (संवाददाता): विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने सोमवार को कांग्रेस नेता जयराम रमेश के उस आरोप का जवाब दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि ह्वस्त्रह्व का दम घोंटा जा रहा है और उसे कमजोर किया जा रहा है। सिंह ने कहा कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की विरासत कमजोर नहीं हो रही है, बल्कि मोदी सरकार के तहत इसके अच्छे नतीजे मिल रहे हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सरकार पर अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए आक्रामक निजीकरण एजेंडा अपनाने का आरोप लगाया था। इसके जवाब में जितेंद्र सिंह ने पिछले 12 वर्षों में अंतरिक्ष क्षेत्र में हुई प्रगति का ज़्योरा दिया और कहा कि मॉडल ह्वस्त्रह्व और इंडस्ट्री का मिलकर काम करना है और वे भारत की अंतरिक्ष कहानी का अगला अध्याय लिख रहे हैं। अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने जयराम रमेश पर सरकार की उपलज़्धियों को कमतर दिखाने की कोशिश करने का आरोप लगाया। आप और आपके जैसे लोग भारत की हर कामयाबी को कमतर आंकने और हर आगे बढ़ते

कदम पर शक करने पर तुले हुए हैं। भारत का स्पेस प्रोग्राम इसका नया शिकार बना है - लेकिन असलियत कुछ और ही है। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, भारत का स्पेस सेज़्टर अब ग्लोबल लेवल पर आगे बढ़ रहा है। यह पहले मुज़्य रूप से सरकार द्वारा चलाया जाने वाला प्रोग्राम था, लेकिन अब यह ह्वस्त्रह्व, इंडस्ट्री और स्पेस स्टार्टअप्स को मिलाकर एक पूरा इकोसिस्टम बन गया है। उन्होंने कहा, भारत के स्पेस प्रोग्राम को कम नहीं किया जा रहा है।

जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत का लक्ष्य हर साल 50 लॉन्च करने का है। उन्होंने कहा इसे बढ़ाया जा रहा है। आइए सबूतों के साथ असलियत को साफ-साफ समझें। ह्वस्त्रह्व को कमजोर नहीं किया जा रहा है। इसे खास मिशनों - जैसे गगनयान, चंद्रयान-4, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन और भविष्य में चांद, शुक्र और मंगल पर जाने वाले मिशनों - पर ज़्यादा ध्यान देने के काबिल बनाया जा रहा है। साथ ही, जैसे-जैसे भारत हर साल 50 लॉन्च के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है, इंडस्ट्री को बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चरिंग करनी होगी, जबकि ह्वस्त्रह्व अगली पीढ़ी की टेज़्नोलॉजी और मिशन विकसित करेगा।

उन्होंने कहा, यह भारत के स्पेस प्रोग्राम का स्वाभाविक विकास है। भारतीय इंडस्ट्री हमेशा से ह्वस्त्रह्व की अहम पार्टनर रही है। आज हमारे युवा अपने रॉकेट और सैटेलाइट बना रहे हैं, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं, प्राइवेट कैपिटल जुटा रहे हैं और अपने स्पेस प्रोग्राम चला रहे हैं। इसका सबसे साफ उदाहरण इस साल 18 जुलाई को देखने को मिला.

सीएम हेमंत सोरेन ने यूएई में फंसे झारखंड के मजदूर को सुरक्षित वापसी के दिए निर्देश

रांची २४/०८ (संवाददाता): झारखंड के मुज़्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को संबंधित अधिकारियों को संयुक्त अबर अमीरात में तीन महीने से अधिक समय से फंसे एक प्रवासी मजदूर की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। राज्य प्रवासन प्रकोष्ठ की टीम लीडर शिखा लाकड़ा ने बताया कि मुज़्यमंत्री के निर्देश के बाद अधिकारियों ने मजदूर की सुरक्षित स्वदेश वापसी सुनिश्चित करने के लिए पश्चिम एशियाई देश में स्थित भारतीय दूतावास से संपर्क किया है।

लाकड़ा ने 'पीटीआई-भाषा' को बताया, मुज़्यमंत्री ने सोमवार सुबह हमें मजदूर की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। हमने संयुक्त

अरब अमीरात स्थित भारतीय दूतावास के प्रतिनिधियों और विदेश मंत्रालय से संपर्क किया है।

उन्होंने बताया कि प्रवासन प्रकोष्ठ ने गिरिडीह जिले के बगोदर थाना क्षेत्र के अटका गांव निवासी रमेश्वर दास की वापसी के लिए आवश्यक दस्तावेज भेज दिए हैं। फंसे हुए प्रवासी मजदूर के परिजनों ने बताया कि वह रोजगार की तलाश में एक ठेकेदार के माध्यम से इस साल 6 मई को पर्यटक वीजा पर दुबई गया था।

अधिकारी ने कहा, परिजनों का दावा है कि पिछले पांच दिनों से उनका रमेश्वर से संपर्क नहीं हो पाया है। उसका मोबाइल फोन बंद है, जिससे परिवार के लोग चिंतित हैं। उनका यह भी कहना है कि वह कर्ज लेकर विदेश गया था। प्रवासी मजदूरों के लिए काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता सिकंदर अली ने रविवार को गांव में रमेश्वर के परिवार से मुलाकात की थी।

तमिलनाडु सरकार का बड़ा फैसला, भारी विरोध के बाद परंदूर एयरपोर्ट प्रोजेज़्ट रद्द

चेन्नई २४/०८ (संवाददाता): तमिलनाडु की राजनीति और बुनियादी ढांचे के विकास को लेकर सोमवार को राज्य विधानसभा के बजट सत्र में एक बड़ा मोड़ देखने को मिला। मुज़्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने विधानसभा में कई ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। एक ओर जहां राज्य सरकार ने स्थानीय ग्रामीणों के व्यापक विरोध और पर्यावरणीय चिंताओं के कारण चेन्नई के दूसरे अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (परंदूर एयरपोर्ट) की योजना को आधिकारिक रूप से रद्द कर दिया, वहीं दूसरी ओर आम जनता को राहत देते हुए मुज़्त रसोई गैस और मुज़्त बस यात्रा के विस्तार जैसी बड़ी जनकल्याणकारी योजनाओं का ऐलान किया।

परंदूर एयरपोर्ट प्रोजेज़्ट का प्रस्ताव पिछली द्रविड़ मुनेत्र

कड़गम (ष्ठरू्ध) सरकार ने अगस्त 2022 में दिया था, जिसमें तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन नोडल एजेंसी थी। हालांकि, इस प्रोजेज़्ट को लेकर पर्यावरण संबंधी चिंताएं उठीं और स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया।

विजय की पार्टी तमिलगा वेट्री कड़गम ने भी प्रदर्शनकारियों का साथ दिया और अब इस प्रोजेज़्ट को रद्द करने का फैसला किया है। हालांकि, ष्ठरू्ध ने ञ्जङ्कय् के इस कदम की आलोचना करते हुए कहा है कि केंद्र सरकार ने भी परंदूर एयरपोर्ट को मंजूरी दी थी। विधानसभा के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए ष्ठरू्ध नेता थंगम थेन्नारासु ने कहा कि चेन्नई के लिए दूसरा एयरपोर्ट बहुत ज़रूरी था, लेकिन विजय की सरकार ने राजनीतिक कारणों से इस योजना को रद्द कर दिया।उन्होंने कहा, परंदूर में एयरपोर्ट होना सबसे अच्छा रहता। राजनीतिक कारणों से परंदूर एयरपोर्ट प्रोजेज़्ट को रद्द करने से आर्थिक नुकसान होगा। कई उद्योग आंध्र प्रदेश की ओर चले जाएंगे। हम पहले ही होसुर एयरपोर्ट का मौका गंवा चुके हैं।

विधानसभा में अपने संबोधन के दौरान, विजय ने यह भी घोषणा की कि हर परिवार को तीन मुज़्त स्रुक्त सिलेंडर दिए जाएंगे और इसकी राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस योजना से पूरे तमिलनाडु में लगभग 1.30 करोड़ परिवारों को फ़ायदा होगा।

विजय ने कहा, यह योजना जनवरी में आने वाले पोंगल त्योहार से लागू की जाएगी और इसके लिए हर साल लगभग 4,000 करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे। जिन परिवारों की सालाना आय 2.5 लाख रुपये से कम है, छोटे और सीमांत किसान परिवार, दिव्यांगजन वाले परिवार और अन्य कमज़ोर वर्गों के परिवारों को इस योजना का लाभ मिलेगा। मुज़्यमंत्री ने वेट्री पयनम योजना के विस्तार की भी घोषणा की, जिसके तहत तमिलनाडु में महिलाओं को मुज़्त बस यात्रा की सुविधा मिलती है। उन्होंने कहा कि अब महिलाएं मेट्रोपॉलिटन और शहरी इलाकों में चलने वाली एज़्सप्रेस, स्रूस्र और डीलज़्स सरकारी बसों में मुज़्त यात्रा कर सकेंगी।

विजय ने कहा कि महिलाएं अब मोफ़ुसिल (बाहरी) और पहाड़ी इलाकों में साधारण बसों में भी मुज़्त यात्रा कर सकेंगी और यह सुविधा इस साल गांधी जयंती से लागू होगी। उन्होंने यह भी साफ़ किया कि आय की कोई सीमा या यात्राओं की संज़्या पर कोई रोक नहीं होगी, और इस योजना के तहत ट्रांसजेंडर भी मुज़्त यात्रा कर सकेंगे।

विविध समाचार

मैदे का इस्तेमाल हर घर में किया जाता है लेकिन क्या आपको पता है कि मैदे से बनी चीजें हमारे स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है या नहीं। आज हम आपको मैदे के बारे में बताएंगे कि मैदा हमारी सेहत को कैसे नुकसान पहुंचाता है। मैदे के कई साइड इफेक्ट होते हैं, जिनका हमें लंबे समय बाद पता चलता है। एक शोध से बात सामने आई है कि मैदे को सफेद रंग ब्लीच से दिया जाता है। इसके ज्यादा सेवन से हमारी सेहत खराब हो सकती है और कई तरह की परेशानियां भी हो सकती है। आइए जानते है मैदे से सेहत को होने वाले नुकसान...

डायबिटीज: मैदे में ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, जिसके सेवन से शुगर लेवल बढ़ जाता है। अगर आप भी मैदे का अधिक सेवन करते है तो संभल जाएं।

पेट की समस्या: मैदे में डाइट्री फाइबर बिल्कुल नहीं होता, इसलिए मैदे से बनी डिश का सेवन करने से ये पूरी तरह से पच नहीं पाता है। इसके सेवन से अक्सर कब्ज की समस्या हो जाती है।

फूड एलर्जी: मैदे में काफी मात्रा में ग्लूटन पाया जाता है जो खाने को लचीला बना कर उसको मुलायम टेक्सचर देता है और फूड एलर्जी का कारण बनता है।

हड्डियां कमजोर: मैदे में प्रोटीन ना होने से शरीर में एसिड बन जाता है, जो हड्डियों से कैल्शियम को कम करके उनको कमजोर कर देता है।

मोटापा: मैदा में स्टार्च की मात्रा बहुत अधिक होती है, जिससे मोटापा बढ़ता है। यही नहीं इससे कोलेस्ट्रॉल स्तर भी बढ़ता है। अगर आप अपना वजन कम करना चाहते है तो मैदे का कम सेवन करें।

आज ही छोड़े रात में लाइट जलाकर सोने की आदत

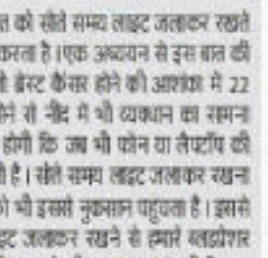

अगर आपकी रात में लाइट जलाकर सोने की आदत है तो सावधान रहें ये आदत बदल डालिए क्योंकि एक रिसर्च से ये बात साबित हुई है कि लाइट जलाकर सोने से आपको गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। हमारे शरीर का एक बायोलॉजिकल क्लॉक सूरज और चांद की रोशनी से नियंत्रित होता रहता है जो कि कृत्रिम रोशनी के कारण गड़बड़ा रहा है। इसलिए कभी भी लाइट जलाकर नहीं सोना चाहिए। यदि हम रात को सोते समय लाइट जलाकर रखते हैं तो ये शरीर में कैंसर कोशिकाओं को एक्टिव करता है। एक अध्ययन से इस बात की पुष्टि हुई है कि सोने के समय अगर रोशनी हो तो ब्रेस्ट कैंसर होने की आशंका में 22 फीसदी का इजाफा होता है। लाइट जलाकर सोने से नींद में भी व्यवधान का सामना करना पड़ता है। आपने खुद ये बात महसूस की होगी कि जब भी फोन या लैपटॉप की लाइट जलती है आपकी नींद आने आप टूट जाती है। सोते समय लाइट जलाकर रखना हमारे मूड पर तो असर डालता है। हमारे दिल को भी इससे नुकसान पहुंचता है। इससे हृदय सम्बंधी बीमारियां हमें घर दबोचती हैं। लाइट जलाकर रखने से हमारे ब्लडप्रेशर पर भी असर पड़ता है। इसके अलावा ये हमारे दिमाग को भी नुकसान पहुंचाती है।

क्या आप मांसपेशियों और चयापचय स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं? और बड़ी संख्या में स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने वाले प्राकृतिक पदार्थ की खोज कर रहे हैं? तो आपको मैलिक एसिड पर विचार करना चाहिए। यह स्वस्थ होने के साथ बहुत सारे लाभ प्रदान करता है।

मैलिक एसिड से दूर करें

क्रोनिक थकान सिंड्रोम...

मैलिक एसिड एक प्राकृतिक पदार्थ है, कि ज्यादातर फलों और सब्जियों के बीच पाया जाता है। जो कि सेब जैसे फलों के साथ जुड़ा होता है, और कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी में परिवर्तित करने के लिए जाना जाता है। यह स्वास्थ्य समस्याएं फाइब्रोमयाल्जिया और क्रोनिक थकान सिंड्रोम के उपचार में लाभदायक होता है। इतना ही नहीं, अगर आप साफ, चमकदार और सॉफ्ट त्वचा चाहते हैं तो आपकी समस्या का हल निश्चित रूप से मैलिक एसिड है। आइए मैलिक एसिड के स्वास्थ्य और सौंदर्य लाभ के बारे में जानकारी लेते हैं।

एनर्जी बढ़ाए

हमें पूर्णरूप से जीने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। अगर आपको भरपूर नींद लेने के बावजूद दिन भर एनर्जी महसूस नहीं होती या आप सुस्त महसूस करते हैं, तो समस्या आपके शरीर के साथ नहीं है बल्कि आपके खान-पान में है। आपके आहार में मैलिक एसिड का अभाव है। मैलिक एसिड के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि यह एनर्जी के स्तर को बढ़ा देता है। यह प्रतिबंध चक्र का एक महत्वपूर्ण घटक है जो आपके शरीर में एनर्जी में प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट में बदल जाता है। यह आपके शरीर में एनर्जी के स्तर के उत्पादन में सुधार करता है।

ओरल स्वच्छता के लिए बेस्ट

मैलिक एसिड आपके ओरल स्वच्छता के लिए अच्छा होता है। यह लार के उत्पादन को बढ़ा कर, मुंह में विषाक्त बैक्टीरिया के स्तर को कम करता है। इससे दांत साफ होते हैं और पीले निशान तेजी से कम होते हैं। इसके अलावा दांतों को सुरक्षा और मजबूती मिलती है। अक्सर, मैलिक एसिड वाणिज्यिक उत्पादों, माउथवॉश और टूथपेस्ट में मिलाया जाता है।

खूबसूरत त्वचा

मैलिक एसिड से भी त्वचा में अद्भुत निखार आता है। मैलिक एसिड त्वचा को लंबे समय तक सुंदर और स्वस्थ रखने में मददगार होता है। यह प्राकृतिक रूप से व्हाइटनिंग एजेंट के रूप में जाना जाता है। जब आप इसे सीधा त्वचा पर लगाते है, तो यह त्वचा को एक्सफोलिएट और सॉफ्ट करता है, साथ ही एजिंग के निशान को भी कम करता है। साथ ही इसके इस्तेमाल से झुर्रियां दूर हो जाती है। इसके अलावा कोलेजन के उत्पादन को बढ़ावा देता है जिससे मुंहासों के सभी लक्षण समाप्त हो जाते है।

दर्द कम करें

मैलिक एसिड शरीर के दर्द को कम करने के लिए भी जाना जाता है। हालांकि, इसके लंबे समय तक परिणाम देखने के लिए इसे आपको नियमित आधार पर लेना होगा। आमतौर पर शरीर के दर्द को कम करने के लिए 48 घंटे का समय पर्याप्त माना जाता है। अब आप जब भी गंभीर दर्द से परेशान होंगे तो आपको पता है कि आपको क्या करना है।

कितना लें मैलिक एसिड

ज्यादातर अध्ययनों और शोधकर्ताओं के अनुसार, प्रतिदिन मैलिक एसिड की 1,200 से 1,800 मिलीग्राम तक राशि लेने की सिफारिश की जाती है। यह क्रोनिक थकान सिंड्रोम जैसी स्वास्थ्य की स्थिति के इलाज के लिए जाना जाता है। हालांकि मैलिक एसिड में विषाक्तता नहीं होती है, लेकिन इसके सेवन से कुछ लोगों का पेट खराब हो सकता है। अगर आपको नियमित आधार पर मैलिक एसिड लेने के लिए सिफारिश की है, तो प्रतिदिन 280 मिलीग्राम लेना, सबसे अच्छा रहता है।

अमृत समान है काले नमक का पानी...

आयुर्वेद के अनुसार काला नमक अपने आहार में शामिल करने से शरीर के कई रोग दूर हो सकते हैं। यह कोलेस्ट्रॉल, मधुमेह, हाई बीपी, डिप्रेशन और पेट की तमाम बीमारियों से मुक्ती दिलाता है क्योंकि इसमें 80 प्रकार के खनिज शामिल हैं। अगर आप सुबह काला नमक और पानी मिला कर पीना शुरू कर दें तो आपको काफी स्वास्थ्य लाभ पहुंच सकता है। कुछ लोगों को अभी पता नहीं है कि सादे नमक का बहुत ज्यादा प्रयोग हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है इसलिए अच्छा होगा कि आप उसे हटा कर काले नमक का सेवन कीजिए।

मोटापा घटाए: यह पाचन को दुरुस्त कर के शरीर की कोशिकाओं तक पोषण पहुंचाता है, जिससे मोटापा कंट्रोल करने में मदद मिलती है। समुद्री नमक छोड़ कर आपको इस नमक को अपने आहार में शामिल करना चाहिए।

जोड़ों के दर्द में आराम दिलाए: मांसपेशियों के दर्द और जोड़ों के दर्द से यह नमक आराम दिलाता है। आपको एक कपड़े में 1 कप काला नमक डाल कर उसे बांध कर पोटली बनानी है। इसके बाद उसे किसी पैन में गरम करें और उससे जोड़ों की सिकाई करें। इसे दुबारा गरम कर के फिर से दिन में दो बार सिकाई करें।

आंत की गैस से छुटकारा दिलाए: अगर गैस से छुटकारा पाना है तो एक कॉपर का बरतन गैस पर चढ़ाएं, फिर उसमें काला नमक डाल कर हल्का चलाएं और जब उसका रंग बदल जाए तब गैस बंद कर दें। फिर इसका आधा चम्मच ले कर एक गिलास पानी में मिक्स कर के पिएं।

सीने की जलन से मुक्ती: क्षारीय प्रकृति होने के नाते यह पेट में जा कर वहां बनने वाले एसिड को काटता है और सीने की जलन तथा एसिडिटी को ठीक करता है।

कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल करे: काला नमक खाने से रक्त पतला होता है जिससे यह पूरे शरीर में आराम से पहुंचता है। ऐसे में आपका हाई कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर ठीक होता है। हाई बीपी है तो नमक की जगह पर खाएं यह मसल स्पैजम और क्रैंप में आराम दिलाए-काला नमक में पोटैशियम होता है जो कि हमारी मांसपेशियों को ठीक से काम करने में मदद करता है। इसलिये काले नमक को रोजाना खाने में शामिल करें जिससे मसल सैंजम और क्रैंप ना हो।

शिशुओं के लिए भी अच्छा: काला नमक छोटे बच्चों के लिए सबसे अच्छा है। यह अपच और कफ की जमावट को सीने से हटाता है। अपने शिशु के भोजन में थोड़ा सा काला नमक रोजाना मिलाएं क्योंकि इससे उनका पेट भी ठीक रहेगा और कफ आदि से भी छुटकारा मिलेगा।

नींद लाने में लाभदायक: अपरिष्कृत नमक में मौजूद खनिज हमारी तंत्रिका तंत्र को शांत करता है। नमक, कोर्टिसोल और एड्रनलाईन, जैसे दो खतरनाक स्ट्रेस हार्मोन को कम करता है। इसलिए इससे रात को अच्छी नींद लाने में मदद मिलती है।

रूसी से मुक्ती दिलाए: अगर आपको रूसी और बाल झड़ने की समस्या है तो काला नमक और टमाटर का जूस हफ्ते में एक दिन सिर में लगाएं। यह रूसी को दूर करेगा और बालों की ग्रोथ को भी बढ़ाएगा।

शरीर करे डिटॉक्स: नमक में काफी खनिज होने की वजह से यह एंटीबैक्टीरियल का काम भी करता है। इसकी वजह से शरीर में मौजूद खतरनाक बैक्टीरिया का नाश होता है।

त्वचा की समस्या: नमक में मौजूद क्रोमियम एक्ने से लड़ता है और सल्फर से त्वचा साफ और कोमल बनती है। इसके अलावा नमक वाला पानी पीने से एग्जिमा और रैश की समस्या दूर होती है।

कैसे बनाएं काला नमक वाला पानी: एक गिलास गुनगुने पानी में आधा छोटा चम्मच काला नमक मिलाइए। फिर इसे चम्मच से मिक्स कीजिए और 24 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद जब सारा नमक पानी में घुल जाए तब इसे पी जाइए एवं किसी भी उपचार को करने से पहले या अन्य किसी समस्या के लिए अपने डॉक्टर से अवश्य संपर्क करें।

LIFE-STYLE

छोटे-छोटे टिप्स कर सकते हैं जिंदगी में बड़े बदलाव

दाम्पत्य को खुशहाल बनाते बेडरूम में सुंदर चित्र

बेडरूम हमारे घर का बहुत ही खास हिस्सा होता है। कई बार बेडरूम में वास्तु दोष होने से उसका बुरा असर हमारे दांपत्य जीवन पर भी पड़ता है। वास्तु टिप्स का उपयोग हमारे बेडरूम में करें तो दांपत्य जीवन में खुशहाली बनी रह सकती है। ये वास्तु टिप्स इस प्रकार हैं...

दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनाए रखने के लिए, पलंग के सामने की दीवार पर सुंदर चित्र लगाने चाहिए। सुंदर चित्रों से मन में शांति की अनुभूति होती है और पलंग के सामने दर्पण नहीं होना चाहिए। अगर पलंग के सामने दर्पण होगा तो आप हमेशा परेशान रहेंगे। बेडरूम में पलंग हमेशा दक्षिण दिशा में रखना चाहिए। सोते समय सिर उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं कर सकते तो पश्चिम दिशा में पलंग रखना चाहिए। इस स्थिति में सोते समय मुंह पूर्व की ओर व सिरहाना पश्चिम की ओर रहना चाहिए। पूर्व की ओर व उत्तर की ओर मुंह करके सोना सुखदायक होता है। दक्षिण की ओर मुख करके नहीं सोना चाहिए। दक्षिण की ओर मुंह करके सोने से नींद नहीं आती है।

दरवाजे से दूरी

बेडरूम में आपका बेड दरवाजे के पास नहीं होना चाहिए यदि ऐसा करेंगे तो चित्त में अशांति व व्याकुलता बनी रहेगी। बेडरूम में खिड़की अवश्य होना चाहिए। सुबह की किरणें बेडरूम में प्रवेश करने से स्वास्थ्य बेहतर रहता है। कभी भी मुख्य द्वार की ओर पैर करके न सोएं।

बेड पर सीधे न पड़े प्रकाश

बेडरूम में ड्रेसिंग टेबल कभी भी खिड़की के सामने न रखें, क्योंकि खिड़की से आने वाला प्रकाश परावर्तित होने के कारण परेशानी उत्पन्न करेगा। पलंग के सामने खिड़की न होकर ठोस दीवार होना चाहिए। बेडरूम में पलंग के दाईं ओर छोटी टेबल आवश्यक वस्तु रखने के लिए रख सकते हैं। बेडरूम में प्रकाश व्यवस्था ऐसी हो कि पलंग पर सीधा प्रकाश नहीं पड़े। प्रकाश सदैव पीछे या बाईं ओर से आना चाहिए। मुख्य बेडरूम नैऋत्य (पश्चिम-दक्षिण) कोण में होना चाहिए। मुख्य बेडरूम वह होता है, जिसमें घर का मालिक सोता है। गलत दिशा में बेडरूम होने पर कमरे में राधा-कृष्ण का प्रेममय फोटो लगाएं। ऐसा करने पर कमरे के वास्तु दोष खत्म हो जाएंगे।

एयरोस्पेस मैनेजमेंट में भविष्य की उड़ान

कुछ वर्षों के दौरान ग्लोबल कमर्शियल एयरोस्पेस सेक्टर महत्वपूर्ण विकास का साक्षी रहा है। एयरोस्पेस सेक्टर में हुए इस विकास की बदौलत ट्रेंड मैनेजर्स की जरूरत पैदा हुई है। इसे देखते हुए हाल ही में कनाडा की एचईसी मांट्रियाल ने एयरोस्पेस मैनेजमेंट में एमबीए डिग्री लॉन्च की है ताकि देश-विदेश में एयरोस्पेस सेक्टर में महत्वपूर्ण पदों पर कार्य करने के इच्छुक युवाओं को प्रशिक्षित किया जा सके।

योग्यताएं जरूरी

एयरोस्पेस इंडस्ट्री में अक्सर मैनेजर्स की शुरुआत साइंटिफिक या टेक्निकल बैकग्राउंड से होती है, जिसके पश्चात वे टीम या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पोजीशंस पर पहुंचते हैं, लेकिन इस कार्य के लिए उनमें कुछ विशिष्ट गुण, कौशल तथा योग्यताएं होनी जरूरी होती है। एयरोस्पेस मैनेजमेंट में एमबीए उन्हें वह कौशल देगा, जिसकी उन्हें इस क्षेत्र में सफल होने के लिए जरूरत पड़ेगी। एयरोवर्ल्ड एमबीए नामक यह प्रोग्राम एक वर्षीय कोर्स है, जिसे एयरोस्पेस में महारत रखने वाले ईबीसी एयरोवर्ल्ड इंस्टीट्यूट के अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों के साथ मिल कर करवाया जाएगा।

बेहतर कॅरियर की संभावनाएं

बोइंग के अनुसार अगले 20 वर्षों के दौरान नए विमानों में से आधे से अधिक की बिक्री चीन तथा भारत जैसे देशों में होगी। नए विमान बनाने में विलम्ब, अनिश्चितता, बड़ा पूंजी निवेश तथा लम्बे समय तक वसूली जैसी बातें जुड़ी होती हैं। ऐसे में एयरोस्पेस इंडस्ट्री को न केवल उच्च दक्षता व कुशलता सहित रणनीतिक दृष्टिकोण वाले इंजीनियर्स व वैज्ञानिक ही नहीं, अच्छी तरह प्रशिक्षित मैनेजर व लीडर्स भी चाहिए। इसलिए एयरोस्पेस मैनेजमेंट में एमबीए से आप इस क्षेत्र में भी कॅरियर की संभावनाएं तलाश सकते हैं। इसमें शुरुआती सैलरी 25 से 30 तक हो सकती है। इसे बाद तजुर्बा बढ़ने के साथ ही सैलरी में भी इजाफा होगा।

रेसिपी

कॅरेमलाईस्ड बनानास्

सामग्री

- 2 बड़े पके हुए केले
- 2 टेबल-स्पून मक्खन
- 2 टेबल-स्पून ब्राउन शुगर
- 1/4 टी-स्पून दालचीनी पाउडर

विधि

प्रत्येक केले को छिलकर, 2 भाग टुकड़ों में काटकर, प्रत्येक टुकड़े को 2 लंबे भाग में काट लें। आपको कुल मिलाकर 8 टुकड़े प्राप्त होंगे। एक तरफ रख दें। एक चौड़े नॉन-स्टिक पैन में मक्खन गरम करें, ब्राउन शुगर डालकर, मध्यम आंच पर 1 से 2 मिनट या शक्कर के पिघलने तक, लगातार हिलाते हुए पका लें। केले डालकर अच्छी तरह मिला लें और मध्यम आंच पर 2 मिनट के लिए, बीच-बीच में हिलाते हुए पका लें। इन कॅरेमलाईस्ड केले के टुकड़ों को एक प्लेट में रखकर, दालचीनी पाउडर छिड़कर गुनगुने तापमान पर परोसें।

दही भल्ले

सामग्री

घोल के लिए: 250 ग्राम मूंग दाल, नमक स्वादअनुसार, **इमली की चटनी के लिए:** 1 कटोरी इमली का पानी, नमक स्वादअनुसार, 2 चम्मच चीनी, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, **अन्य सामग्री:** 100 ग्राम दही, 4 चम्मच चीनी, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाऊडर, काला नमक स्वादअनुसार, **तलने के लिए:** तेल

विधि

दाल को पानी में 5-6 घंटे के लिए भिगो दीजिए, फिर उसे मिक्सी में पीस लें। पीसते समय पानी न मिलाएं। अब पैन में तेल गरम करें। पीसी हुई दाल के पेस्ट की पकौड़ी बनाकर फ्राई कर लें। तलने के बाद पकौड़ों को पेपर पर निकाल लें और हल्के गरम पानी में भिगो दें। अब दही को छानकर उसमें हल्का पानी मिलाएं। दही में चीनी, नमक, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर डालकर मिक्स करें। अब पैन में इमली का पानी डालकर उबालें, फिर उसमें नमक, चीनी, लाल मिर्च पाउडर और जीरा पाउडर मिलाकर चटनी तैयार करें। गरम पानी में भिगोई हुई पकौड़ियों को निकाल कर दही के साथ मिलाएं। ऊपर से इमली की चटनी डालें। काला नमक, जीरा पाउडर और लाल मिर्च पाउडर छिड़क कर सर्व करें।

कलिंग समाचार

संपादकीय

उन्नाव पीड़िता को थोड़ी राहत

सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव बलात्कार मामले में दोषी पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा दी गई जमानत पर रोक लगा दी है। मु य न्यायाधीश सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने दिल्ली हाईकोर्ट के 23 दिसंबर के उस आदेश के लागू होने पर स्टे ऑर्डर जारी किया, जिसमें सेंगर की आजीवन कारावास की सजा निलंबित कर उन्हें अपील लंबित रहने तक जमानत दी गई थी। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, विशेष तथ्यों को देखते हुए, जहां दोषी एक अलग अपराध में भी सजा काट रहा है, हम दिल्ली हाईकोर्ट के 23 दिसंबर 2025 के आदेश को लागू करने पर रोक लगाते हैं। इस प्रकार, आरोपी को उक्त आदेश के तहत रिहा नहीं किया जाएगा। इस फैसले से एक बड़ी राहत पीड़िता को मिली है, क्योंकि अब यह तो तय हो गया है कि बलात्कार के दोष में कुलदीप सिंह सेंगर जेल में ही रहेगा, अब भी पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के एक अलग मामले में वह 10 वर्ष की सजा काट ही रहा है। इसमें उसे जमानत नहीं मिली है और अगली सुनवाई 4 ह ते बाद है। लेकिन अगर इस मामले में भी जमानत मिल जाती तब तो पीड़िता के लिए खतरा और ज्यादा बढ़ जाता। सेंगर ने केवल एक नाबालिग मासूम का बलात्कार ही नहीं किया, बल्कि अपने राजनैतिक दबदबे का इस्तेमाल उसकी इंसाफ की लड़ाई को रोकने में भी किया। इसलिए जब हाईकोर्ट ने सेंगर को जमानत दी थी, तो उसने इस नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाई थी। उसका साथ देने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता योगिता भयाना सामने आईं। हालांकि यह देखकर बेहद अफसोस हुआ कि इंसाफ के लिए लड़ रहे इन लोगों को पुलिस प्रशासन ने कुचलने की तमाम कोशिशें कीं। इंडिया गेट से लेकर संसद और हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट के सामने तक जहां भी कुलदीप सेंगर को जमानत मिलने का विरोध करने के लिए पीड़िता के साथ लोग इकट्ठे हुए उन्हें वहां से बलपूर्वक भगाने की कोशिशें हुईं। समझ नहीं आता कि आखिर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों से किस बात का खतरा सरकार को दिखाई देता है। देश में कितने ही मामले ऐसे सामने आते हैं जहां गुंडे कभी रेस्तरां, कभी पार्क में बैठे लोगों को परेशान करने, प्रताड़ित करने पहुंच जाते हैं। तब पुलिस पता नहीं कहां गायब हो जाती है। अभी देहरादून में अंजेल चकमा नाम के युवा को नस्लभेदी नफरत के कारण मार दिया गया। उसे चायनीज़ और मोमो जैसे शब्द बोलकर अपमानित किया गया। वह कहता रहा कि वह भारतीय है, फिर भी उसकी जान ले ली गई। हालांकि वह भारतीय न भी होता, सच में चीन या किसी और देश का नागरिक होता, तब भी नस्लीय नफरत और हिंसा के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। लेकिन ऐसे उत्पीड़न जब हो रहे होते हैं, तब पुलिस वहां नहीं पहुंचती। भाजपा के शासन में पुलिस का भी राजनीतिकरण करने के जो आरोप लगते हैं, वो ऐसी घटनाओं के बाद सही लगते हैं। कुलदीप सेंगर मामले में शर्मनाक बात यह है कि भाजपा के कई नेता उसके समर्थन में खुलकर आ गए हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह ने सेंगर को जमानत देने का स्वागत किया था, योगी सरकार में मंत्री ओ पी राजभर ने भी पीड़िता का मजाक उड़ाते हुए कहा था कि उसका घर उन्नाव में है तो दिल्ली में प्रदर्शन की क्या जरूरत। इसके बाद भाजपा पर कुलदीप सेंगर को राजनीतिक संरक्षण देने का जो आरोप लगा है, वह भी प्रमाणित होता दिखाई देता है। सब जानते हैं कि बलात्कार का गंभीर आरोप लगने के बावजूद लंबे समय तक कुलदीप सेंगर को गिर तार नहीं किया गया। भाजपा ने लगातार इस मामले में लीपापोती की। अभी जमानत मिलने के बाद जब पीड़िता, उसकी मां और योगिता भयाना आदि विरोध के लिए सड़कों पर थे तो कुछ लोग सेंगर के समर्थन में पोस्टर लेकर उनसे भिड़ने आ गए। इनमें एक महिला भी थी, जो बार-बार कह रही थी कि इस मामले का राजनीतकरण किया जा रहा है। अफसोस की बात ये है कि मु यधारा का मीडिया ऐसे लोगों को बराबरी से कवरेज दे रहा था, मानो यही निष्पक्ष पत्रकारिता की कसौटी है। हालांकि एक पत्रकार ने सेंगर के समर्थन में आवाज उठा रही महिला से पूछ लिया कि आपकी बेटी के साथ ऐसा होता क्या तब भी आप बलात्कारी के लिए ऐसे ही सामने आती, तो वह महिला बिना जवाब दिए चली गई।

कुपोषण दूर करने में सब्जियों की महत्वपूर्ण भूमिका

भारत डोगरा

सृजन संस्था की ओर से जहां ऐसी खेती के लिए तकनीकी सहायता, बीज व विभिन्न साज-सामान के रूप में सहायता दी जाती है, वहां मिट्टी व जल संरक्षण के कार्यों का योगदान भी कम नहीं है। जल-संरक्षण कार्यों जैसे तालाब से मिट्टी-गाद हटाने से बेहतर सिंचाई उपलब्ध होती है। तालाबों से निकली मिट्टी-गाद से खेत का उपजाऊपन बढ़ता है। कुछ किसानों को प्राकृतिक कृषि केन्द्र स्थापित करने की सहायता दी जाती है जहां गोबर, गोमूत्र आदि की खाद व हानिकारक कीटों से बचाव के उत्पाद तैयार किए जाते हैं।

भारतीय परिस्थितियों में यदि पोषण सुधारने का कोई एक सबसे सक्षम उपाय चुनना हो तो वह है सब्जियों की निर्धन परिवारों व जनसाधारण को अधिक उपलब्धि। सभी सब्जियों में कम या अधिक पोषण गुण है और यदि विविध सब्जियां पर्याप्त मात्रा में नियमित तौर पर भोजन में शामिल रहें तो पोषण का संतुलन अपने आप बना रहता है। विभिन्न विटामिन व खनिज तत्त्वों की उपलब्धि के लिए सब्जियां सबसे बेहतर स्रोत हैं। फाईबर भी उनसे अच्छा उपलब्ध होता हे।

सब्जियों से हमें वे एंटीआक्सीडेंट प्राप्त होते हैं जो बीमारी व संक्रमण से रक्षा करने में बहुत सहायक हैं। विभिन्न सब्जियां कुछ विशेष रोगों व स्वास्थ्य समस्याओं से बचाने में या उनके उपचार में सहायक हैं। आंखों के स्वास्थ्य की ही बात करें तो गाजर व हरी पत्तीदार सब्जियां इसके लिए विशेष लाभदायक हैं। फ़ैमिली गेम

इधर सब्जियों के स्वास्थ्य गुणों पर एक सवाल भी उठाया गया है कि अधिक कीटनाशक दवाओं व रासायनिक खाद के उपयोग से इनके स्वास्थ्य गुणों में कमी आती है व कुछ गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। अत- प्राकृतिक खेती से प्राप्त सब्जियों को ही स्वास्थ्य व पोषण की दृष्टि से सर्वोत्तम माना गया है।

इस संदर्भ में देखें तो सृजन संस्था द्वारा सब्जी का उत्पादन प्राकृतिक कृषि पद्धति से बढ़ाने के अभियान का स्वागत होना चाहिए, विशेषकर यह देखते हुए कि इसमें छोटे किसानों को और उनमें भी महिला किसानों को प्राथमिकता दी गई है। निर्धन आदिवासी व दलित किसानों पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस तरह न केवल पौष्टिक सब्जियों के उत्पादन को बढ़ाया जा रहा है, अपितु यह ऐसे किसानों के खेतों पर विशेष तौर पर बढ़ाया जा रहा है जिनके परिवार को बेहतर पोषण की अधिक जरूरत है।

इस संदर्भ में एक सवाल यह उठता है कि छोटे किसानों के पास तो कम भूमि है जिस पर उन्हें अपनी जरूरत का अनाज, दलहन आदि भी उगाना है तो फिर उनके पास अधिक सब्जी उगाने के लिए कृषि भूमि कै से उपलब्ध होगी। इस समस्या को सुलझाने के लिए सृजन ने मल्टी लेयर या बहु-स्तरीय सब्जी की खेती का प्रसार किया है जिसमें विभिन्न स्तरों पर तरह-तरह की सब्जियां एक साथ उगाई जाती हैं, कुछ जमीन के नीचे, कुछ सब्जियां छोटे पौधों पर, कुछ बड़े पौधों पर तो कुछ ऊपर की ओर बेल के ऊपर रहती हैं। इसके लिए बांस, रस्सी व तार लगाकर बेलों को ऊपर तक बढ़ने का सहारा दिया जाता है जिनसे उनमें लगी सब्जी अधिक सुरक्षित भी रहती है। ऐसे बगीचों को प्रतिकूल मौसम व पशुओं से सुरक्षित भी किया जाता है। किराने का सामान

ऐसे बगीचे के नियोजन में इस विषय की बड़ी समझ होती है कि किस पौधे को किस के साथ लगाना उचित है, मिट्टी के पोषण की दृष्टि से कैसा मिलन उचित है, कौन सा कोमल पौधा किसी बड़े पौधे की छाया में पनप सकता है आदि। इस तरह की समझ, निष्ठा और मेहनत के आधार पर बहुत से किसान बहुत कम भूमि में ही विविध तरह की सब्जियों का अच्छा उत्पादन प्राप्त कर रहे हैं। मौसम के अनुसार विभिन्न सब्जियां अलग-अलग समय पर बिक्री के लिए भी उपलब्ध होती रहती हैं व इस तरह आय की निरंतरता भी बनी रहती है। सृजन संस्था की ओर से जहां ऐसी खेती के लिए तकनीकी सहायता, बीज व विभिन्न साज-सामान के रूप में सहायता दी जाती है, वहां मिट्टी व जल संरक्षण के कार्यों का योगदान भी कम नहीं है। जल-संरक्षण कार्यों जैसे तालाब से मिट्टी-गाद हटाने से बेहतर सिंचाई उपलब्ध होती है। तालाबों से निकली मिट्टी-गाद से खेत का उपजाऊपन बढ़ता है।

कुछ किसानों को प्राकृतिक कृषि केन्द्र स्थापित करने की सहायता दी जाती है जहां गोबर, गोमूत्र आदि की खाद व हानिकारक कीटों से बचाव के उत्पाद तैयार किए जाते हैं। इस तरह अगर सब्जियों की बगिया में प्राकृतिक पद्धति अपनाने से सहायता मिलती है वहां यह संभावना भी बढ़ जाती है कि जल-संरक्षण और प्राकृतिक खेती का यह मिलन किसानों को इतना पसंद आ जाए कि वह अपनी पूर्ण खेती के लिए भी इसे अपना लें। चित्रकूट जिले के मऊ ब्लाक में कोल बस्तियों गुइयां खुर्द और गुईयां कलां में भी इसी मिलन से आदिवासी किसानों ने प्रगति की है। यहां के जल-संरक्षण कार्यों में लगभग 10 लाख रुपए का खर्च आया जिनमें से 70 प्रतिशत तक तो इन आदिवासी परिवारों में मजदूरी के रूप में वितरित हो गए। विटामिन और फूड सप्लीमेंट खरीदें

इस कार्य की सफलता के लिए इन परिवारों की नजदीकी भागेदारी प्राप्त की गई व उन्हें गांव विकास समितियों के रूप में संगठित किया गया। इसके साथ प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण दिया गया। इस तकनीक से खर्च बहुत कम होने की संभावना ने भी इन छोटे किसानों को आकर्षित किया।

श्याम पहले मजदूर के रूप में इधर-उधर भटक रहा था, पर अब यह नए अवसर उपलब्ध होने पर उसने अपनी खेती सुधारने पर ध्यान केंद्रित किया। उसकी पत्नी सविता सब्जी की खेती में नेत्तृत्व देने वाली महिला के रूप में सामने आई। उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें सृजन ने एक सोलर पंप की सुविधा भी उपलब्ध करवाई।

इसी प्रखंड में लपांव गांव में भी इस प्रयास ने अच्छी प्रगति की। किरण ने अपना छोटा पर अति उत्पादक बगीचा गर्व से दिखाया। यहां बंदरों से रक्षा के लिए सृजन ने एक हरा नेट भी उपलब्ध करवाया है। परिवार के सभी सदस्य मिल कर यहां बहुत मेहनत व निष्ठा से सब्जियां उगाते हैं। किरण ने बताया कि प्राकृतिक पद्धति से उत्पादित सब्जी की गुणवत्ता इतनी अच्छी मानी जा रही है कि व्यापारी बगीचे तक पहुंचकर सब्जी खरीद कर ले जाते हैं। किरण के ससुर ब्रज बिहारी ने बताया कि कुछ सप्ताह पहले तक उनकी आंख इतनी कमजोर हो गई थी कि आप्रेशन करवाने की बात चल रही थी, पर अपने बगीचे में उत्पन्न सब्जी व विशेषकर चौलाई खाने से आंखों में बहुत तेजी से सुधार हो गया। इस परिवार ने घर के पास एक किचन गार्डन व फलों को छोटा बगीचा भी तैयार किया है।इसी गांव में आशा ने घर के पास छोटा सा खाली स्थान देखकर वहां सुंदर किचन गार्डन तैयार कर लिया है। इससे परिवार का पोषण बहुत सुधर गया है व साथ में पड़ौसियों, आने वाले मेहमानों को भी आशा कुछ सब्जी का उपहार देती रही हैं। यहां एक गोलाकार ढंग की ऐसी सिंचाई व्यवस्था बनाई गई है कि सभी पौधों तक पानी पहुंच जाता है।

पुष्पा एक दलित महिला है जिसने अभी किचन गार्डन लगाना शुरू ही किया था पर वह इस प्रयास से बहुत उत्साहित थी। इस तरह कार्यक्रम के आरंभ होने के एक वर्ष के भीतर ही कई परिवार इससे जुड़ गए थे।

इसके अतिरिक्त सृजन ने अन्य सहयोगी संस्थाओं जैसे समाज सेवा संस्थान, अंत्योदय व युवा कौशल विकास मंडल के सहयोग से सब्जी की वाटिकाओं का प्रसार अनेक अन्य गांवों में भी किया है। हमीरपुर जिले (उत्तर प्रदेश) व कुछ अन्य स्थानों पर इन किसान परिवारों ने बताया कि उनके पोषण में भी सुधार हुआ है व वर्ष में विभिन्न समय पर इस प्रयास से कुछ नकद आय भी प्राप्त होती रहती है। मानिकपुर प्रखंड (जिला चित्रकूट) में सब्जी उगाने वाले समुदाय के किसानों ने कहा कि चाहे परंपरागत तौर पर उनका अपना सब्जी उगाने का बहुत अनुभव रहा है, फिर भी प्राकृतिक पद्धति व बहुस्तरीय सब्जी उत्पादन के इस मॉडल में उन्हें भी बहुत कुछ सीखने को मिला है।

जी राम जी या रोजगार गारंटी को जै राम जी

अरविन्द मोहन

दुनिया भर की आर्थिक नीतियों और विकास पर नजर रखने वालों की यह चिंता मनरेगा के शुरुआती परिणामों और क्रांतिकारी स्वरूप को लेकर है। यूपीए सरकार द्वारा शुरू इस योजना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले काफी कुछ कह चुके हैं लेकिन इसके लाभ को देखकर उन्होंने भी सत्ता में आने पर इसे हटाने की हि मत नहीं की। और जब करोना के लक्षण दिखते ही एक बार में राष्ट्रव्यापी लाकड़ाउन का जैसा गलत फैसला हो गया तब मनरेगा ने जिस तरह समाज के सबसे कमजोर समूह की मदद की उसे देखकर वे भी प्रभावित हुए और मनरेगा का बजट बढ़ा ही।

मात्र दो दिन के हंगामे या चर्चा के बाद जो बिल पास हो चुका है और जिस पर राष्ट्रपति के भी दस्तखत हो चुके हैं उसको लेकर अभी भी विपक्ष और %षडयंत्रकारियों% को कोसना भी इस बात का प्रमाण हो सकता है कि सरकार ने मनरेगा के स्वरूप में जो बदलाव किए हैं उनके पीछे प्रशासनिक और वित्तीय मसलों के साथ राजनैतिक मसले भी जुड़े हुए हैं।

और अगर यह बिल पेश करने वाले मंत्री शिवराज सिंह चौहान अभी भी इस पर राजनैतिक बयान दे रहे हैं तो यह भाजपा द्वारा अपनी चलाने और उसका राजनैतिक लाभ लेने का ही प्रमाण है। यह सही है कि सं या-बल में हारा विपक्ष तो इस योजना से गांधी का नाम हटाने को मु य मुद्दा बना रहा है लेकिन दुनिया भर के प्रमुख अर्थशास्त्रियों समेत देश के बौद्धिक जमात में भी इसे लेकर बेचैनी जाहिर हो रही है, मनरेगा लाने के पीछे मु य शक्ति रहीं सोनिया गांधी और लगभग पूरा विपक्ष इसके खिलाफ ताल ठोंक रहा है तो एनडीए के घटक दलों से ही नहीं भाजपा के अंदर से भी कुछ असहमति के स्वर सुनाई दे रहे हैं। जोजेफ़ स्टिगलिट, थामस पिकेटी, जे स गालब्रेथ, इजाबेले फेरारेस, डेरिक हैमिल्टन, मारिआना मझाकूटो, इमरान वेलोडिया, रैंडल व्रे और पवलिना चेरनेवा जैसे याति प्राप्त अर्थशास्त्रियों ने साझा बयान जारी करके मनरेगा के स्वरूप में हुए बदलावों पर आपत्ति जताई है।

दुनिया भर की आर्थिक नीतियों और विकास पर नजर रखने वालों की यह चिंता मनरेगा के शुरुआती परिणामों और क्रांतिकारी स्वरूप को लेकर है। यूपीए सरकार द्वारा शुरू इस योजना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले काफी कुछ कह चुके हैं लेकिन इसके लाभ को देखकर उन्होंने भी सत्ता में आने पर इसे हटाने की हि मत नहीं की। और जब करोना के लक्षण दिखते ही एक बार में राष्ट्रव्यापी लाकड़ाउन का जैसा गलत फैसला हो गया तब मनरेगा ने जिस तरह समाज के सबसे कमजोर समूह की मदद की उसे देखकर वे भी प्रभावित हुए और मनरेगा का बजट बढ़ा ही। इधर फिर से मनरेगा उपेक्षित होने लगा था और उसकी गलतियों और कमियों पर तो ध्यान नहीं ही दिया जा रहा था, उसमें घोटाले बढ़े थे और किसी मामले में दोषियों को सजा देने का काम नहीं हुआ। मजदूरी देने में भी बहुत देरी होने से उसका असली मकसद ही खत्म हो रहा था।

लंबे अनुभव से कुछ बदलावों की जरूरत मानी जा रही थी। नए कानून में रोजगार के दिनों की सं या सौ से बढ़ाकर सवा सौ और खेती के समय दो महीने मनरेगा के काम बंद रखने जैसे दो बदलावों को आप इस श्रेणी में रखना चाहें तो रख सकते हैं लेकिन जैसा कानून बना है उसमें तो पूरी योजना ही हाशिये पर आ जाएगी, फिर ये सुधार किस काम के होंगे।

बीस साल पहले जब महाराष्ट्र के छोटे अनुभव को आधार बनाकर देश भर के लिए रोजगार गारंटी का कानून बना तो दुनिया का ध्यान उसकी तरफ लगा हालांकि तब भारत विश्व गुरु होने का दावा नहीं करता था। लंबी सार्वजनिक और संसदीय चर्चा के बाद यह कानून बना था। संसदीय समिति तो भाजपा के नेता कल्याण सिंह की अगुवाई वाली थी और इसमें भी सर्वस मति बनी थी। तब भी इसके खर्च और लाभ को लेकर इसका विरोध करने वाले थे लेकिन मु यत- यूपीए की अध्यक्ष सोनिया गांधी के अड़े रहने से यह कानून बना। इसके बाद ही शिक्षा का अधिकार, भोजन का अधिकार और सूचना का अधिकार जैसे अधिकार आधारित कानून बने। जब पाँच करोड़ सबसे गरीब परिवारों को 200 करोड़ कार्यदिवस का रोजगार दिया गया तो दुनिया भर में इसकी धूम मची क्योंकि इस पैमाने पर गरीबों को सीधी मदद और गाँव तथा पिछड़े इलाके में उपयोगी सामाजिक परिसंपत्तियों के निर्माण की ऐसी कोई योजना तब तक विश्व में कहीं भी नहीं चल रही थी। रोजगार की गारंटी का पक्ष तो विलक्षण था ही, इसमें आधे से ज्यादा कामगार महिलाएं थी, दलितों और आदिवासियों का अनुपात चालीस फीसदी था। कुंआ, तालाब, सड़क, फलदार पेड़, छोटे बांध जैसी परिसंपतियों का निर्माण और जीर्णोद्धार गांवों की सहमति से हुआ तो उसका लाभ उनको लगातार हुआ। प्रशासनिक खर्च पांच फीसदी से भी कम था। रोजगार और परिसंपत्तियों के निर्माण के साथ तीसरा और सबसे बड़ा लाभ यह हुआ की ग्रामीण क्षेत्र में औसत दिहाड़ी मजदूरी बढ़ गई।

सैकड़ों अध्ययनों से इनके लाभ ही जाहिर हुए। कुछ कमजोरियां भी दिखीं और कुछ नए सुझाव भी आये जिनहे लागू करना मुश्किल न था। खर्च भी हर अनुमान से नीचे रहा - जीडीपी के एक फीसदी से कम।

जब तक सोनिया गांधी ने अलग से वीडियो जारी करके अपने इस प्रिय कानून को बचाने के लिए संघर्ष की घोषणा नहीं की तब तक कांग्रेस और विपक्ष के विरोध का मु य मुद्दा इस योजना से महात्मा गांधी का नाम हटाने और अंग्रेजी-हिन्दी के लंबे और ऊटपटांग नाम से बनाए गए %जी राम जी' ही बनता दिख रहा था। वे इसके सामाजिक, आर्थिक और अन्य पक्षों को भूल से गए लगते थे। भाजपा के गांधी विरोध और राम जी प्रेम की राजनीति अनजानी नहीं है।

लेकिन बिल के स्वरूप के बदलाव से पीछे ज्यादा बड़े कारण है। राज्यों से बिना चर्चा उन्हें ही रोजगार का गारंटर बनाया गया है लेकिन पैसा देना न देना केंद्र के विवेक पर निर्भर कर दिया गया है। इससे ज्यादा परेशानी का सवाल धन और खर्च का है जिसमें पहले राज्यों का हिस्सा दस फीसदी था तो अब चालीस फीसदी हो गया है। इस योजना की जरूरत सबसे ज्यादा गरीब राज्यों को है लेकिन संसाधन जुटाने के बोझ में उनको कोई रियायत नहीं मिली है। अब अगर वे चालीस फीसदी खर्च के डर से आगे नहीं बढ़ेंगे तो केंद्र वैसे ही हाथ धोकर किनारे खड़ा हो जाएगा। केंद्र के विवेक के और भी विषय हैं तो राज्यों पर जि मेवारियों के सारे बोझ हैं। रोजगार देना, बेरोजगारी भत्ता देना, देर से मुगतां पर क्षतिपूर्ति देना और पर्याप्त फंड का इंतजाम जैसे सारे बोझ राज्यों के सिर मध दी गए हैं और उनसे कोई चर्चा नहीं हुई है। अब भाजपा शासित राज्यों में तो ज्यादा नाराजगी नहीं दिखती लेकिन विपक्ष शासित राज्य पहले से परेशान हैं। पश्चिम बंगाल को तो पिछले तीन साल से मनरेगा के लिए ही कोई धन नहीं मिला है।

कांग्रेस और विपक्ष शासित राज्यों की तरफ से उलटी प्रतिक्रिया आने लगी है तो एनडीए शासित राज्यों से भी असहमति के स्वर सुनाई दे रहे हैं। खुद भाजपा के कई लोग ने प्रावधानों को लेकर सशंकित हैं। पर बिहार चुनाव जीतने के बाद सरकार जिस मूड में आ गई है उसमे ऐसी असहमतियों की कोई परवाह नहीं दिखती। श्रम कानूनों को हटाकर विवादास्पद संहिताऐं लाना, निजी क्षेत्र के लिए एटमी क्षेत्र खोलना, बीमा क्षेत्र में शत प्रतिशत विदेशी पूंजी को अनुमति देना, विदेशी विश्वविद्यालयों के भारत आने, आनलाइन गेमिंग कानून में बदलाव और प्रस्तावित बीज कानू वगैरह यही बताते हैं कि सरकार एकदम मनमानी पर आ गई है।

विविध समाचार

पुलिस ने 2 देसी पिस्तौल के साथ दो गैंगस्टर को बठिंडा में किया गिरफ्तार

चंडीगढ। पंजाब में हथियार और ड्रग्स तस्करों के खिलाफ पुलिस लगातार अभियान चलाते हुए कार्रवाई कर रही है। आए दिन तस्करों को पुलिस गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से हथियार और मादक पदार्थ बरामद कर रही है। इसी कड़ी में बठिंडा में दो आरोपियों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने एक्स पर पोस्ट कर जानकारी दी है, जिसमें बताया है, "पंजाब की एंटी–गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) ने बठिंडा में दो आरोपियों को पकड़ा है। इनके पास से .32 बोर की दो देसी पिस्तौल और पांच कारतूस बरामद किए हैं।" डीजीपी ने बताया कि शुरुआती जांच से पता चला है कि दोनों आरोपी फिरोजपुर इलाके में सक्रिय एक जेल में बंद गैंगस्टर द्वारा चलाए जा रहे आपराधिक नेटवर्क से जुड़े हैं। आरोपियों का आपराधिक बैकग्राउंड है और वे हत्या की कोशिश और आर्म्स एक्ट के उल्लंघन समेत कई मामलों में शामिल रहे हैं। सिविल लाइन्स पुलिस स्टेशन बठिंडा में मामला दर्ज किया गया है। नेटवर्क के पिछले और अगले कनेक्शन का पता लगाने और इसमें शामिल अन्य साथियों की पहचान करने के लिए आगे की जांच जारी है। पंजाब पुलिस संगठित आपराधिक नेटवर्क को खत्म करने और पूरे पंजाब में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके पहले 8 जून को डीजीपी ने बताया था कि अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए सीमा पार अवैध हथियार तस्करी और हवाला नेटवर्क का भंडाफोड़ करते हुए एक अफगान नागरिक सहित चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 8 अत्याधुनिक पिस्तौल और 7 कारतूस बरामद किए गए थे। आरोपी विदेश स्थित एक तस्कर के संपर्क में थे, जो गुप्त स्थानों के माध्यम से अवैध हथियारों की खेप की आपूर्ति करता था। आरोपियों के खिलाफ इस्लामाबाद पुलिस स्टेशन और अमृतसर के गेट हकीमा पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई थी। इसके पहले 3 जून को पंजाब डीजीपी की ओर से बताया गया था कि पंजाब में नशा और अवैध हथियारों के कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत अमृतसर पुलिस कमिश्नरेट को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने सीमा पार से संचालित एक अंतरराज्यीय हथियार और ड्रग तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 2.225 किलोग्राम हेरोइन, छह अत्याधुनिक पिस्तौल और 12 कारतूस बरामद किए गए।

पंजाब का चुनाव तंत्र एसआईआर के लिए पूरी तरह तैयार : मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनिंदिता मित्रा

चंडीगढ। पंजाब की मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनिंदिता मित्रा ने कहा कि देश में लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने के लिए मतदाता सूची की सटीकता अत्यंत महत्वपूर्ण है। वह भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार, पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय द्वारा आयोजित तीन–दिवसीय राज्य–स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन सत्र को संबोधित कर रही थीं। यह कार्यक्रम विशेष गहन पुनरीक्षण–2026 के तहत घर–घर जाकर की जाने वाली गणना (गिनती) के अभ्यास के संबंध में था, जो 25 जून, 2026 से पूरे राज्य में शुरू होने जा रहा है। 8 जून से 10 जून, 2026 तक आयोजित इस राज्य–स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में पंजाब के 23 जिलों के सभी 117 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले लगभग 650 अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया। प्रतिभागियों में अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी , चुनाव तहसीलदार, जिला मास्टर लेवल ट्रेनर और तकनीकी कर्मचारी शामिल थे। उन्होंने कहा कि इस प्रशिक्षण के पूरा होने के साथ ही चुनाव विभाग राज्य में विशेष गहन पुनरीक्षण आयोजित करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। श्रीमती मित्रा ने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण–2026 के दौरान भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ लागू करना सभी हितधारकों की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने आगे बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण के संबंध में बूथ स्तर के अधिकारिया और बूथ स्तर के एजेंटों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम 11 जून से 24 जून, 2026 तक पंजाब के सभी जिलों में आयोजित किए जाएंगे। इस अवसर पर, श्रीमती अनिंदिता मित्रा ने प्रतिभागियों के साथ बातचीत भी की और विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम से जुड़े संदेहों को दूर करने के लिए उनके प्रश्नों के उत्तर दिए। इसके अलावा, आईटी विशेषज्ञों ने पुनरीक्षण अभ्यास के प्रभावी कार्यान्वयन की सुविधा के लिए प्रतिभागियों को विभिन्न आईटी मॉड्यूल्स पर विशेष व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया।

कनाडा में ड्यूटी के दौरान पंजाब मूल के पुलिस अधिकारी की मौत, अस्पताल से भागे आरोपी ने जानबूझकर चढ़ाई गाड़ी

नंगल। कनाडा के ओंटारियो प्रांत में ड्यूटी के दौरान एक खौफनाक घटना में पंजाब मूल के पुलिस अफसर तरुण बाली की मौत हो गई है। ओंटारियो प्रांतीय पुलिस में सेवारत कांस्टेबल तरुण बाली पर एक 18 वर्षीय संदिग्ध ने जानबूझकर वाहन चढ़ा दिया, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं और बाद में उन्होंने दम तोड़ दिया। इस घटना ने उनके पैतृक शहर पंजाब के रूपनगर जिले के नंगल और कनाडा में बसे भारतीय समुदाय को गहरे सदमे में डाल दिया है। ओंटारियो पुलिस ने मंगलवार को उनकी मौत की आधिकारिक पुष्टि करते हुए बताया कि वह डफरिन डिटैचमेंट के साथ तैनात थे और पिछले ढाई साल से पुलिस सेवा में कार्यरत थे। ओंटारियो पुलिस के अनुसार, यह घटना मंगलवार दोपहर करीब 12.30 बजे हर्स्ट इलाके में केंडल कंसेशन रोड 7 और कंसेशन रोड 6 के पास हुई। जेम्स बे डिटैचमेंट के साथ स्पेशल ड्यूटी पर गई पुलिस की एक टीम वहां जांच कर रही थी, तभी एक 18 वर्षीय आरोपी ने पुलिस अधिकारियों पर तेजी से गाड़ी चढ़ा दी। शुरुआती जांच में सामने आया है कि यह आरोपी घटना से कुछ समय पहले ही एक अस्पताल से भाग निकला था। इस भीषण हमले में तरुण बाली को गंभीर चोटें आईं और तमाम मेडिकल प्रयासों के बावजूद उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। उनके साथ मौजूद एक अन्य पुलिस अधिकारी भी इस घटना में गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसका फिलहाल अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उस पर फर्स्ट–डिग्री मर्डर का मामला दर्ज किया है। तरुण बाली नंगल के रहने वाले थे और अशोक बाली व नीना बाली के छोटे बेटे थे। टोरंटो बसने से पहले यह परिवार नंगल के शिवालिक एवेन्यू में रहता था। करीब ढाई साल पहले तरुण ने ओंटारियो पुलिस जॉइन की थी और लगभग दो साल पहले ही उनकी शादी कनाडा में रहने वाली पंजाब मूल की युवती कोमल से हुई थी। उनकी असामयिक मौत से परिवार, रिश्तेदार और जानने वाले गहरे सदमे में हैं। तरुण के बलिदान और सेवा को सम्मान देने के लिए, उनका पार्थिव शरीर पोस्टमार्टम और अन्य कानूनी प्रक्रियाओं के लिए टोरंटो के मुख्य कोरोनर कार्यालय ले जाया जाएगा। लगभग 10 घंटे के इस लंबे सफर में आपातकालीन वाहनों का एक विशेष सम्मान काफिला उनके पार्थिव शरीर के साथ मौजूद रहेगा। तरुण बाली के निधन की खबर मिलते ही उनके पैतृक शहर नंगल में मातम की लहर दौड़ गई है। स्थानीय लोग उन्हें एक बेहद समर्पित और मेहनती युवा के रूप में याद कर रहे हैं, जिसने परिवार के साथ विदेश जाकर कानून व्यवस्था बनाए रखने और लोगों की सेवा करने का अपना सपना पूरा किया था। इंडो–कनाडाई समुदाय, दोस्तों और रिश्तेदारों की ओर से लगातार श्रद्धांजलि दी जा रही है। समुदाय के लोग कांस्टेबल तरुण बाली को एक साहसी अधिकारी के रूप में याद कर रहे हैं, जिन्होंने जनता की रक्षा करते हुए ड्यूटी की वेदी पर अपने प्राणों की आहुति दे दी।

वेस्ट हलके में भाजपा की मंडल प्रधानों की सूची पर उठे सवाल, दलित समाज को उचित प्रतिनिधित्व न मिलने से अंदरखाते पनपने लगा रोष

जालंधर। जालंधर भाजपा शहरी ने मंगलवार को वेस्ट विधानसभा हलके और कैंट विधानसभा हलके में मंडल प्रधानों के नामों की घोषणा की। वेस्ट हलके में जो सूची जारी की गई उस सूची पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। बेशक खुले मंच पर विरोध तेज नहीं हुआ है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक कथित रूप से दबी जुबान में इस बात को लेकर बहस शुरू हो गई है कि इस सूची में दलित भाईचारे के किसी नेता को प्रमुखता से अग्रिम पंक्ति में नहीं रखा गया। वेस्ट विधानसभा हलका एक रिजर्व सीट है और पूर्व सांसद सुशील रिंकू और पूर्व विधायक शीतल अंगुराल खुद दोनों ही दलित समाज से हैं। अब इतने बड़े नेताओं के दलित समाज से होने के बावजूद मंडल प्रधानों की सूची में दलित समाज को अग्रिम पंक्ति में न रखना पार्टी के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकता है। वेस्ट विधानसभा हलके की सूची में 5 नाम हैं। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार इन नामों में न तो कोई नाम रविदास भाईचारे से संबंधित है, न ही वाल्मीकि भाईचारे से है।

सबसे बड़ी बात वेस्ट विधानसभा हलके में अच्छा खासा वोटबैंक भगत बिरादरी का है लेकिन मंडल प्रधानों की सूची में भी भगत बिरादरी को प्रतिनिधित्व ही नहीं दिया गया इसलिए अंदरखाते भार्गव कैंप में विरोध के कुछ स्वर उठ सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक एक और बात यह भी सामने आई है कि प्रधानों के नाम जारी करने की सूची में एक नेता की बात ज्यादा मानी गई और दूसरे के चहेतों को सूची से दूर रखा गया। राजनीतिक विश्लेषकों की नजर में ये तो पार्टी के अंदर की राजनीति है इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं है लेकिन रिजर्व सीट पर किसी दलित नेता को मंडल प्रधानगी की सूची में अग्रिम पंक्ति में न रखना अनुचित है। हो सकता है कि भाजपा के विरोधी दल आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दलित नेताओं की इस अनदेखी को मुद्दा बना लें क्योंकि आम आदमी पार्टी ने तो भगत बिरादरी से विधायक मोहिंदर भगत को तो कैबिनेट मंत्री तक बनाया हुआ है। एक अनुमान के मुताबिक वेस्ट विधानसभा हलके में 60 प्रतिशत से ज्यादा वोटर दलित समुदाय (रविदास भाईचारा, वाल्मीकि भाईचारा, भगत बिरादरी) से हैं इसलिए इनका प्रतिनिधित्व मंडलों की सूची में मिलना आवश्यक है।

उल्लेखनीय है कि मंडल प्रधानों की सूची के मुताबिक बस्ती गुजां से ऋषि बहल, बस्ती दानिशमंदा से मनीष बल, घास मंडी मंडल से अजय ठाकुर, माडल हाउस से सोनू चौहान और बस्ती पीरदाद से प्रदीप खुल्लर को जिम्मेवारी सौंपी गई है। इसी रोषस्वरूप कबीर टाइगर फोर्स के प्रधान अरुण संदल ने तो साफ कहा दिया है कि लगता है भाजपा दलित समुदाय से दूर ही रहना चाहती है। भाजपा नहीं चाहती कि दलित समुदाय पार्टी में ऊपर उठे, हां दलितों को वर्कर बनाकर वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करना ही उसकी रणनीति में जरूर शामिल है। दलित शुरू से ही वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किए जाते रहे हैं पर अब इस सोच को हर पार्टी को बदलना होगा। हालांकि वैस्ट हल्का पूरी तरह से आरक्षित है यह सब पता होने के बावजूद ऐसा भेदभाव करना दलित समाज का सरेआम अपमान करने समान है।

अभी भी समय है भाजपा अपनी सोच और रणनीति को बदले और दलित प्रेम दिखाकर पार्टी के ऊंचे पदों तक लेकर जाए ताकि दलितों को उनका बनता हक मिल सके।

2027 चुनाव में जालंधर कैंट से भाजपा का विधायक बनना तय : अमित तनेजा

जालंधर। भारतीय जनता पार्टी जालंधर कैंट विधानसभा के सभी नवनियुक्त सातों मंडल अध्यक्ष आज वरिष्ठ भाजपा नेता अमित तनेजा के निवास पर शिष्टाचार भेंट हेतु पहुंचे। इस अवसर पर भाजपा जिला महामंत्री श्री अमरजीत गोल्डी जी विशेष रूप से उपस्थित रहे। बैठक के दौरान संगठन की मजबूती, कार्यकर्ताओं के विस्तार, जनसंपर्क अभियानों तथा जालंधर कैंट विधानसभा में मिशन 2027 को सफल बनाने को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक को संबोधित करते हुए अमित तनेजा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जनकल्याणकारी नीतियों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व तथा कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत के बल पर पंजाब में भाजपा का जनाधार लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में जालंधर कैंट विधानसभा क्षेत्र से भाजपा की जीत सुनिश्चित होगी और यहां से भाजपा का विधायक बनना तय है। उन्होंने कहा कि पार्टी नेतृत्व द्वारा नियुक्त किए गए सभी मंडल अध्यक्ष अनुभवी, कर्मठ एवं संगठन के प्रति समर्पित कार्यकर्ता हैं। इनके नेतृत्व में संगठन और अधिक सशक्त होगा तथा पार्टी की नीतियों को घर–घर तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाएगी। उन्होंने सभी नवनियुक्त मंडल अध्यक्षों को सफल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भाजपा कार्यकर्ता सेवा, सुशासन और राष्ट्रहित की भावना के साथ जनता के बीच कार्य करते रहेंगे। जिला महामंत्री श्री अमरजीत गोल्डी जी ने कहा कि संगठन की वास्तविक शक्ति बूथ स्तर के कार्यकर्ता होते हैं। उन्होंने सभी मंडल अध्यक्षों से संगठनात्मक गतिविधियों को गति देने, नए कार्यकर्ताओं को जोड़ने तथा केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जन–जन तक पहुंचाने का आह्वान किया।

पूर्व सांसद खन्ना मिले पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद से

होशियारपुर। पूर्व सांसद अविनाश राय खन्ना डी.ए.वी. शिक्षण संस्थानों के 100 वर्ष पूरे होने तथा कनवोकेशन समारोह के उपलक्ष्य में पूर्व राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद से मिले। खन्ना ने पूर्व राष्ट्रपति को बताया कि डी.ए.वी. शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिष्ठित संस्थान है। उन्होंने बताया कि इन संस्थानों का मुख्य उद्देश्य आधुनिक शिक्षा के साथ–साथ वैदिक परंपराओं और नैतिक मूल्यों का प्रसार करना है। डी.ए.वी. संस्थानों का आदर्श स्लोगन "तमसो मा ज्योतिर्गमय" है जिसका अर्थ है कि हे ईश्वर हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। खन्ना ने बताया कि डी.ए.वी. शिक्षण संस्थान अपनी उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा, शानदार।

Printed, Published,Edited, & Owned by Prakash Kumar Dhal, Printed at Promodini Publication, Main road , Chhend colony , Rourkela-15 & Published at ECR-73, Chhend Colony, Rourkela-15, Editor : Prakash kumar Dhal, Email:kalingasamachar@gmail.com , Mob: 9439951525, Ph. 0661-2646999

ओडिशा समाचार

कलिंग समाचार | राउरकेला, मंगलवार 25 अगस्त 2026 | पृष्ठ-6

पुनर्वास पैकेज के अंतर्गत 385 परिवारों को 15.86 करोड़ रुपये से अधिक का मुआवजा तथा 103 व्यक्तियों को संविदा रोजगार प्रदान

राउरकेला २४/०८ (संवाददाता): राउरकेला इस्पात संयंत्र (आरएसपी) अपने विस्तारण परियोजना के लिए भूमि खाली कराने हेतु स्थानातरित किए जा रहे परिवारों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दुहराते हुए उन्हें शीघ्रातिशीघ्र मुआवजा एवं पुनर्वास पैकेज प्रदान कर रहा है। संयंत्र की यह विस्तारण परियोजना उसकी उत्पादन क्षमता को दोगुना करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

12 जून 2026 तक आरएसपी द्वारा 385 परिवारों को 15.86 करोड़ रुपये से अधिक की मुआवजा राशि वितरित की जा चुकी है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी मुआवजा मामलों का अत्यंत सावधानी एवं पारदर्शिता के साथ निपटान हो, इस्पात संयंत्र ने अब तक 103 व्यक्तियों को संविदा आधार रोजगार भी उपलज्ध कराया है, जिससे स्थानातरित परिवारों के लिए स्थायी आय का स्रोत सुनिश्चित हो पाया है।

उल्लेखनीय है कि, इन सभी संविदा कर्मचारियों को 22,500 रुपये मासिक प्रारंभिक वेतन के साथ-साथ सभी वैधानिक सुविधाएँ प्रदान की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त, उनके परिवार अब चिकित्सा सुविधाओं के भी पात्र हो गए हैं। सुचारु पुनर्वास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पूर्व में 184 कुटियों में रहने वाले परिवारों को अस्थायी आश्रयों में स्थानांतरित किया जा चुका है।

इन परिवारों के स्थायी पुनर्वास हेतु देवगाँव के निकट एक उपयुक्त क्षेत्र में आवासीय भूखंड विकसित किए जा रहे हैं। इन भूखंडों में व्यापक सड़क संपर्क, जल निकासी व्यवस्था, विद्युत एवं जलापूर्ति जैसी मूलभूत सुविधाएँ उपलज्ध कराई जा रही हैं, ताकि परिवार अपने स्वयं के घरों का निर्माण कर सकें।

राउरकेला इस्पात संयंत्र इस उद्देश्य के प्रति दृढ़तापूर्वक प्रतिबद्ध है कि औद्योगिक विकास स्थानीय समुदायों के हितों के साथ पूर्ण सामंजस्य में आगे बढ़े। त्वरित विज्ञीय सहायता, रोजगार सृजन और टिकाऊ आधारभूत संरचना के विकास के माध्यम से संगठन पुनर्वास प्रक्रिया से जुड़े परिवारों के लिए एक सुरक्षित, सज़्मानजनक और स्थिर भविष्य सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयासरत है।

ट्रेलर की टक्कर से वृद्ध गंभीर

राउरकेला २४/०८ (संवाददाता): सुंदरगढ़ जिले के हेमगिर थाना अंतर्गत कांधडुड़ा गांव में रविवार की शाम को ट्रेलर की टक्कर से वृद्ध गिर गए। गंभीर अवस्था में उन्हें पहले हेमगिर सरकार अस्पताल फिर वहां से बेहतर इलाज के लिए सुंदरगढ़ अस्पताल स्थानांतरित किया गया है। कांधडुड़ा गांव निवासी 60 वर्षीय नंदलाल भोई रविवार शाम को पैदल सड़क पर जा रहे थे तभी कोयला लेकर जा रहे ट्रेलर की टक्कर से उन्हें गंभीर चोट लगी। गांव वालों को इसका पता चलने के बाद वे वहां पहुंचे और उन्हें लेकर हेमगिर सरकारी अस्पताल गए जहां से नंदलाल को सुंदरगढ़ अस्पताल भेजा गया है। घटना के बाद चालक ट्रेलर लेकर फ़रार हो गया।

600 जेल वार्डर के पद खाली, दो साल से नहीं हुई नियुक्ति, डीजी बोले-इन्हें भरने की तैयारी चल रही

भुवनेश्वर २४/०८ (संवाददाता):जेल में जमीनी स्तर पर सुरक्षा की जिज़्मेदारी वार्डर की होती है। हालांकि राज्य की सभी जेलों में अपेक्षित संज़्या में वार्डर की कमी है। राज्य में 600 से ज्यादा वार्डर पद खाली पड़े हैं। दो साल से भर्ती बंद होने से जेल सुरक्षा में बाधा आ रही है।

चौद्वार, झारपड़ा, बारीपदा और बरहमपुर जैसी विशेष जेलों में भी यही स्थिति है। जेलों में अपराध बढ़ रहे हैं और कैदियों की संज़्या भी। लेकिन जेल की सुरक्षा के लिए वार्डरों की नियुक्ति नहीं की जा रही है। डीजी जेल अमृत मोहन प्रसाद ने बताया कि इस खाली पड़े इन पदों को भरने के लिए तैयारी चल रही है। जल्द ही खाली पदों को भर दिया जाएगा।

ओडिशा में 87 जेल हैं। नियमानुसार राज्य की सभी जेलों में 2100 वार्डर की आवश्यकता है। लेकिन वर्तमान में 1500 वार्डर से काम चल रहा है। इस हिसाब से 30 फीसदी वार्डर पद खाली है।

दो साल पहले राज्य सरकार ने 219 वार्डर पद भरने के लिए राज्य सरकार ने मंजूरी दी थी। हालांकि वह भी आज तक नहीं भरे गए हैं। कटक के चौद्वार जेल के लिए आवश्यक वार्डर संज़्या 126 हैए लेकिन यहां सिर्फ 100 वार्डर काम कर रहे हैं। कई वर्षों से 26 वार्डरों की यहां नियुक्ति नहीं हुई है।

बरहमपुर जेल में 85 वार्डर की आवश्यकता है परंतु यहां भी 15 वार्डर कम हैं। बारीपदा जेल के लिए 65 वार्डर चाहिएए परंतु यहां 15 वार्डर कम हैं। भुवनेश्वर झारपाड़ा जेल की स्वीकृत संज़्या 65 हैए लेकिन 50 वार्डर काम कर रहे हैंए 15 वार्डर भुवनेश्वर की जेल में भी कम हैं। हालांकि इसके उलट इन सभी जेलों में कैदियों की संज़्या नियमानुसार जितनी होनी चाहिएए उससे कहीं ज्यादा है।इसलिए वार्डरों की संज़्या घटने से ड्यूटी स्टाफ पर दबाव बढ़ रहा है। जेल में कैदियों की सुरक्षाए अनुशासनए चिकित्सा उपचार से संबंधित जानकारी इकट्ठा करने जैसे काम वार्डर ग्राउंड जीरो से करते हैं।हालाकिए कर्मचारियों की कमी के कारण ये बुनियादी काम ठीक से नहीं हो पाते हैं।ऐसे में आए दिन जेल में अफ़रातफ़री मची रहती है और कैदियों के भागने की भी खबरें सामने आती रहती हैं। वर्तमान समय में सभी विशेष जेलों में कैदियों की संज़्या बढ़ गयी है। ऐसे में इनकी देखभाल के लिए वार्डर पद भी बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। हालांकिए वार्डर पद बढ़ाना तो दूर पहले से अनुमोदित पद भी खाली हैंए जिससे जेल अधिकारी चिंतित हैं।इस संदर्भ में हाई कोर्ट ने भी चिंता जताई है।

मोहन माझी ने कालाहांडी में बड़ी परियोजनाओं की शुरुआत की

कालाहांडी २४/०८ (संवाददाता):ओडिशा सरकार ने कालाहांडी जिले में एक बड़ा विकास अभियान शुरू किया, जिसमें मुज़्यमंत्री मोहन चरण माझी ने 891.39 करोड़ रुपये की 3,612 परियोजनाओं का उद्घाटन किया और आधारशिला रखी। इन परियोजनाओं का अनावरण कालाहांडी उत्सव घुमुरा-2026 के समापन दिवस पर किया गया, जहाँ मुज़्यमंत्री मुज़्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। अधिकारियों ने बताया कि ये परियोजनाएँ कई क्षेत्रों में फैली हुई हैं और इनका उद्देश्य पूरे जिले में बुनियादी ढाँचे के विकास में तेज़ी लाना और सार्वजनिक सुविधाओं में सुधार करना है। यह पहल राज्य सरकार की संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने की व्यापक रणनीति का हिस्सा है, खासकर पश्चिमी ओडिशा में।

धार्मिक यात्रा और सांस्कृतिक समारोह आधिकारिक कार्यक्रम से पहले, मुज़्यमंत्री माझी ने कालाहांडी की अधिष्ठात्री देवी माँ मानिकेश्वरी के दर्शन किए और पूजा-अर्चना की। बाद में, उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम में कालाहांडी उत्सव घुमुरा-2026 के समापन समारोह में भाग लिया। सांस्कृतिक समारोहों के हिस्से के रूप में, पहली बार कालाहांडी की कला, संस्कृति और विरासत को प्रदर्शित करने वाला एक ड्रोन शो आयोजित किया गया, जिसे देखने के लिए बड़ी संज़्या में लोग आए और इसने जिले की समृद्ध परंपराओं को उजागर किया।

प्रमुख सिंचाई और बांध परियोजनाओं की घोषणा शहीद रेंडो माझी मंच पर सभा को संबोधित करते हुए, मुज़्यमंत्री ने कालाहांडी के लिए रावल उतेई सिंचाई परियोजना की घोषणा की, जिसे अनुमानित 3,325 करोड़ रुपये की लागत से लागू किया जाएगा। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि लगभग 950 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया, और कहा कि कालाहांडी के विकास के लिए कुल 1,600 करोड़ रुपये से अधिक आवंटित किए गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि 3,350 करोड़ रुपये से अधिक की अनुमानित लागत वाली रावल उतेई परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार कर ली गई है और केंद्रीय जल आयोग द्वारा अनुमोदित कर दी गई है। सिंचाई और आर्थिक विकास को बढ़ावा अधिकारियों ने कहा कि इन परियोजनाओं के शुभारंभ और प्रमुख घोषणाओं से कालाहांडी जिले में सिंचाई क्षमता में काफी वृद्धि होने, बुनियादी ढाँचे को मजबूत करने और समग्र आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलने की उज़्मीद है, जिससे किसानों और निवासियों दोनों को फायदा होगा। निकट भविष्य में बेलगाँव के पास तेल नदी पर 505.98 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से एक बांध बनाया जाएगा। इस अवसर पर बोलते हुए, मुज़्यमंत्री मोहन माझी ने कहा कि इस कार्यक्रम के दौरान

संबलपुर में तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई

संबलपुर २४/०८ (संवाददाता): संबलपुर जिला के रेढ़ाखोल आबकारी टीम ने पश्चिम बंगाल के नादिया जिला के दो और ओडिशा के कटक जिला के दो तस्करों को 32 किलो गांजा और एक टाटा इंडिगो कार के साथ गिरज़्तार किया।

यह चारों आरोपित बऊद जिला से गांजा लेकर रेढ़ाखोल के रास्ते पश्चिम बंगाल जा रहे थे। चारों के खिलाफएनडीपीएस एज़्ट के तहत अपराध दर्ज कर बुधवार के दिन न्यायिक हिरासत में रेढ़ाखोल उपकारा भेज दिया गया। इस बारे में जानकारी देते हुए रेढ़ाखोल आबकारी इंस्पेज़्टर जाधव पधान ने बताया कि मंगलवार की आधी रात जब आबकारी टीम गश्ती पर निकली थी तभी रेढ़ाखोल थाना अंतर्गत बिशीपाली चौक के निकट बऊद जिला के ओर से आती सफेद रंग की एक टाटा इंडिगो कार को रोककर तलाशी ली तब दो बड़े प्लास्टिक बैग में भर्ती 32 किलो गांजा मिला। ऐसे में कार में सवार चार व्यक्ति को तुरंत हिरासत में ले लिया गया और पूछताछ के बाद बुधवार के दिन चारों को गिरज़्तार कर लिया गया।

महांगा डबल मर्डर केस में हाई कोर्ट ने सुनाया फैसला, 9 को उम्रकैद

कटक २४/०८ (संवाददाता): हाईकोट ने बहुचर्चित माहांगा डबल मर्डर मामले में फैसला सुनाते हुए 9 आरोपियों को दोषी करार दिया। उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। वहींए एक आरोपी को अदालत ने बरी कर दिया है। इस मामले की सुनवाई पिछले 22 अप्रैल को हाईकोर्ट में खत्म हुई थी।

हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई को खत्म कर फैसले को सुरक्षित रखा था और बुधवार को राय घोषित करते हुए यह सजा सुनाई है। विदित है किए 2 जनवरी वर्ष 2021 को भाजपा के नेता कुलमणि बराल और उनके सहयोगी दिव्यसिंह बराल की बहुत ही बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। घटना के बाद मृतक के बेटे रमाकांत बराल की ओर से सालेपुर थाने में दायर की गई थी। जिसमें कुल 13 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। जिनमें से तीन आरोपी फ़रार हैं। हालांकिए इस मामले में तत्कालीन मंत्री प्रताप जेना के खिलाफ भी केस दर्ज हुआ था।उस घटना में रणजीत बराल की ओर से सालेपुर के जेएमएफ़सी अदालत में प्रोटेस्ट पिटीशन दाखिल की गई थी। जिसकी सुनवाई करते हुए अदालत ने विधायक प्रताप जेना के खिलाफ भादवि की धारा 302ए 120 ;बी द्धए 506 के तहत कॉग्निजेंट स्वीकार किया था और उसके बाद श्री जेना को अदालत ने समन जारी किया था।उस निर्देश को चुनौती देते हुए विधायक प्रताप जेना की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। उस मामले की सुनवाई को खत्म कर हाईकोर्ट राय को सुरक्षित रखा है।

आरएसपी के सिंटर प्लांट-3 में अभिनव पहल से परिचालन विश्वसनीयता एवं दक्षता में वृद्धि

राउरकेला २४/०८ (संवाददाता): राउरकेला इस्पात संयंत्र (आरएसपी) के सिंटर प्लांट-3 (एसपी-3) में परिचालन उत्कृष्टता तथा सतत अनुरक्षण पद्धतियों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए प्रत्येक विंड मेन स्पिलेज हॉपर के लिए पृथक डबल कोन डाइवर्टर वाल्व (डीसीडीवी) की स्थापना संबंधी एक अभिनव पहल को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया गया है। इस पहल का उद्देश्य स्पिलेज हैंडलिंग प्रणाली की दक्षता एवं विश्वसनीयता में सुधार करना तथा प्रणाली में सज़्शन लॉस को उल्लेखनीय रूप से कम करना है।

पूर्व में एक डीसीडीवी को दो स्पिलेज हॉपरों से जोड़ा गया था, जिसके कारण लंबे स्पिलेज लेग, तीव्र मोड़ तथा कई मध्यवर्ती सेज़्शन बन जाते थे। इस व्यवस्था के कारण अज़्सर अत्यधिक घिसाव, सज़्शन लॉस, स्पिलेज लेग का जाम होना तथा सामग्री का जमाव जैसी समस्याएँ उत्पन्न होती थीं, जिससे बार-बार परिचालन बाधित होता था तथा सज़्शन लीकेज को रोकने के लिए अधिक अनुरक्षण की आवश्यकता पड़ती थी।

इन चुनौतियों से निपटने हेतु एसपी-3 में हाल ही में दो नए समर्पित डीसीडीवी सफलतापूर्वक स्थापित किए गए हैं। नई व्यवस्था के तहत कन्वेयिंग लाइनों में मोड़ों और मध्यवर्ती सेज़्शनों की संज़्या कम होने से स्पिलेज हैंडलिंग मार्ग अधिक सुव्यवस्थित हो गया है। परिणामस्वरूप, सामग्री प्रवाह अधिक सुचारु हुआ है, चोकिंग में कमी आई है तथा बेल्ट से जुड़ी स्पिलेज हैंडलिंग प्रणाली की परिचालन स्थिरता में सुधार हुआ है।

इस पहल से सज़्शन लॉस में कमी, उपकरणों के घिसाव में न्यूनता तथा प्रणाली की विश्वसनीयता में वृद्धि जैसे उत्साहजनक परिणाम प्राप्त हुए हैं। साथ ही, डाउनटाइम एवं अनुरक्षण हस्तक्षेपों में कमी आने से संयंत्र की समग्र परिचालन दक्षता में भी वृद्धि हुई है।

परिचालन लाभों के अतिरिक्त, यह परियोजना कार्यस्थल सुरक्षा एवं बेहतर हाउसकीपिंग व्यवस्था सुनिश्चित करने में भी सहायक सिद्ध हो रही है। सामग्री रिसाव एवं चोकिंग में कमी आने से संकरे स्थानों पर हस्तचालित (मैनुअल) अनुरक्षण गतिविधियाँ घटी हैं तथा संपूर्ण प्रणाली में स्वच्छता मानकों में सुधार हुआ है। इस पहल के सकारात्मक परिणामों से उत्साहित होकर एसपी-3 ने विज़ वर्ष 2026-27 के दौरान शेष स्पिलेज हॉपरों के लिए आठ और पृथक डीसीडीवी स्थापित करने की योजना बनाई है। इस पहल से दीर्घकालिक परिचालन एवं अनुरक्षण लाभ प्राप्त होने के साथ-साथ परिसंपज़ि प्रबंधन पद्धतियाँ और अधिक सुदृढ़ होंगी तथा संयंत्र की उत्पादकता में वृद्धि होगी।